रूड़की का प्रथम व एक मात्र हिन्दी दैनिक

परम नागरिक

यानि केवल पत्रकारिता

Now Visit us:
www.paramnagrik.in

आर.एन.आई. सं. UTTHIN/2011/36627
डाक पंजीयन- जी U/ADO/DDN/03/2024-2026

वर्ष 15 अंक 27 कुल पृष्ठ 8 रुड़की (हरिद्वार) रविवार, 23 फरवरी, 2025 मूल्य ₹ 3.00

देश में वित्तीय समावेशन में बड़ी भूमिका निभा रहा यूपीआई

डिजिटल लेनदेन में हिस्सेदारी बढकर हुई 84 प्रतिशत

आरएनएस

नई दिल्ली। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) की देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है और वित्त वर्ष 24 में भारत में हुए पांच डिजिटल लेनदेन में से चार यूपीआई के माध्यम से हुए थे। देश के सभी डिजिटल लेनदेन में यूपीआई की हिस्सेदारी बढकर 84 प्रतिशत हो गई है। फिनटेक कंसल्टिंग और एडवाइजरी फर्म द डिजिटल फिफ्थ की रिपोर्ट में कहा गया कि यूपीआई एक पेमेंट सिस्टम से कहीं अधिक है और भारत के लिए यह एक पूरे इकोसिस्टम के रूप में काम करता है।

द डिजिटल फिफ्थ के संस्थापक और सीईओ समीर सिंह जैनी ने कहा, ष्यूपीआई प्रति माह 16 अरब लेनदेन हैंडल करता है और 2030 के अंत तक इसके 3 गुना बढने का अनुमान है। ऐसे में मजबूत बुनियादी ढांचे की भूमिका सर्वोपरि हो जाती है।ष उन्होंने कहा कि रियल-टाइम में धोखाधड़ी का पता लगाना, क्लाउड-नेटिव आर्किटेक्चर और स्केलेबल, डुअल-कोर स्विच अब वैकल्पिक नहीं हैं, बल्कि वे सुरक्षित और फेल-प्रूफ डिजिटल पेमेंट सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।

2021 से 2024 तक यूपीआई लेनदेन में 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है और यह सालाना आधार पर बढकर 172 अरब लेनदेन तक पहुंच गया है। डिजिटल लेनदेन में यूपीआई की हिस्सेदारी सबसे अधिक है और यह कार्ड-आधारित तथा वॉलेट लेनदेन से कहीं आगे निकल गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि 3 करोड़ से अधिक मर्चेंट यूपीआई से जुड़े हुए हैं। मर्चेंट-टू-कस्टमर सेगमेंट 67 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर के साथ पीयर-टू-पीयर (पी2पी) लेनदेन की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रहा है।

कैग रिपोर्ट : फॉरेटस डिविजन ऑडिट में मिली काफी गड़बड़ी

प्रतिपूरक वनीकरण को आवंटित धनराशि से खरीदे आईफोन-लैपटॉप

आरएनएस

देहरादून। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) को उत्तराखड के फॉरेटस डिविजन ऑडिट में काफी गड़बड़ी मिली है। कैग रिपोर्ट के अनुसार, फॉरेस्ट डिविजन ने प्रतिपूरक वनीकरण (कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन) के लिए आवंटित ध नराशि का इस्तेमाल आईफोन, लैपटॉप, फ्रिज और कूलर की खरीद, भवनों का नवीनीकरण, कोर्ट केस में किया।

2019-2022 की अवधि में प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए) के कामकाज पर बनाई गई कैग रिपोर्ट से पता चला है कि 13.86 करोड़ रुपये प्रतिपूरक वनरोपण के अलावा विभिन्न गतिविधियों के लिए डायवर्ट किए गए थे। जिसके तहत नॉन फॉरेस्ट पर्पस (प्रयोजन), जैसे उद्योग या बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि पर अनिवार्य रूप से भूमि के कम से कम समान क्षेत्र पर वनरोपण की कोशिश की जाती है।

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, सीएएमपीए के दिशा-निर्देशों के अनुसार, धनराशि प्राप्त होने के बाद, एक साल या दो मौसमों के अंदर वनरोपण किया जाना चाहिए। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि 37 मामलों में, फाइनल क्लीयरेंस मिलने के आठ साल से ज्यादा समय बाद प्रतिपूरक वनरोपण किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है, ष्इसके परिणामस्वरूप प्रतिपूरक वनरोपण बढ़ाने में 11.54 करोड़ रुपये की लागत बढ़ गई।ष रिपोर्ट में लगाए गए पेड़ों की लो सर्वाइवल की बात भी कही गई, जो 33.51 प्रतिशत है। वहीं वन अनुसंध ान संस्थान के अनुसार यह अनिवार्य 60-65 फीसदी से काफी कम है।

रिपोर्ट में कहा गया है, श्पांच डिविजन 1,204.04 हेक्टेयर भूमि प्रतिपूरक वनरोपण के लिए उपयुक्त नहीं थी। भूमि की अनुपयुक्तता से पता चलता है कि डीएफओ द्वारा पेश किए गए उपयुक्तता प्रमाणपत्र गलत थे और भूमि की वास्तविक स्थिति का पता लगाए बिना जारी किए गए थे। विभाग ने उनकी लापरवाही के लिए संबंधित डीएफओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।श इसके अलावा, राज्य सरकार ने सीएएमपीए के अनुरोध के बावजूद 2019-20 से 2021-22 तक 275.34 करोड़ रुपये की ब्याज देनदारी का भुगतान नहीं किया।

शीर्ष अदालत ने जनहित याचिका को किया खारिज

एससी सूची में किसी समुदाय को शामिल करना संसद का अधिकार : सुको

ईएमएस

नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति (एससी) सूची में किसी भी समुदाय को शामिल करने या उसमें परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को है। जस्टिस बीआर गवई की अगुआई वाली बेंच ने इस मामले में दाखिल याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए उसे खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि पूरे देश में आरे-कटिका (खटीक) समुदाय को अनुसूचित जाति (एससी) सूची में शामिल किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने साफ रूप से कहा कि जजों के पास एससी सूची में कोई बदलाव करने का अधिकार नहीं है। जस्टिस गवई ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि ऐसी याचिका कैसे स्वीकार्य हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट पहले ही कई बार इस मुद्दे को साफ कर चुका है। जब याचिकाकर्ता के वकील ने

हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की अनुमति मांगी, तो बेंच ने जवाब दिया कि हाईकोर्ट के पास भी ऐसा कोई अधिकार नहीं है। केवल संसद ही यह कर सकती है। बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि कोर्ट के पास अनुसूचित जाति सूची में किसी भी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार नहीं है।

याचिकाकर्ता का तर्क था कि आरे-कटिका (खटीक) समुदाय, जो हिंदू समुदाय का एक भाग है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है। इस समुदाय के लोग मुख्य रूप से भेड़-बकरियों का वध और मांस बिक्री का काम करते हैं और समाज से अलग-थलग रहते हैं। कुछ राज्यों में यह समुदाय अनुसूचित जाति (एससी) में आते हैं, जबकि अन्य राज्यों में इसे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में रखा गया है।

कोर्ट ने मणिपुर के 2023 के एक मामले का हवाला दिया, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) में शामिल करने पर विचार करने का निर्देश दिया था। इस फैसले के बाद राज्य में दंगे और हिंसा भड़क उठी थी। रिव्यू पिटिशन के बाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश को निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का जिक्र करते हुए साफ कहा कि जातियों की श्रेणी में बदलाव करने का अधिकार केवल संसद को है न कि अदालतों को।

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पारित करने पर जताई आपत्ति

ईएमएस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा करते हुए 30 से 40 पृष्ठों का आदेश पारित करने पर आपत्ति जताई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की युगलपीठ हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में जो कुछ हो रहा है, वह घृणित है। अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा करते समय हाईकोर्ट की ओर से 30-40 पृष्ठ लिखना, निचली अदालत को यह संकेत देने जैसा है कि आपके पास दोषी ठहराने के लिए यह एक कारण है। मूलत: यह एक दोषसिद्धि आदेश है। एससी ध ोखाधड़ी के एक मामले में चिकित्सक आधार खेड़ा की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

आधार खेड़ा ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसने 6 फरवरी को अपने 34 पृष्ठ के आदेश में उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था। खेड़ा की ओर से पेश सीनियर वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता के पिता ही याचिकाकर्ता और उसकी मां के जरिए से फर्म का संचालन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने उनकी भूमिका को उनके पिता के बराबर बताया। याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने से इनकार करने में इस तथ्य की अनदेखी कर दी कि वह मामले की जांच में शामिल हुए थे। वकील ने दलील दी कि मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है। इसके बाद, पीठ ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और खेड़ा को मामले में गिरफ्तारी से राहत दी।

बिजली वितरण कंपनियों को निजी क्षेत्र को सौंपेगी सरकार

नई दिल्ली। देश के सभी राज्यों की बिजली वितरण कंपनियां भारी घाटे में चल रही हैं। बिजली कंपनियों के ऊपर 6.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज में डूबी हुई हैं। भारत में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारी बिजली कंपनियों को आर्थिक सहायता भी दे रही हैंउसके बाद भी इन कंपनियों का घाटा बढ़ता ही चला जा रहा है। केंद्र सरकार एक बार फिर बिजली कंपनियों को बेलआउट पैकेज देने पर विचार कर रही है। ताकि कंपनियों को दिवालिया होने से बचाया जा सके। 2021 के बाद पहली बार केंद्र सरकार, राज्य की बिजली कंपनियों को बेल आउट पैकेज देने पर विचार कर रही है। 2021 में 3 लाख करोड़ का बेल आउट पैकेज केंद्र सरकार ने दिया था। उसके बाद भी विद्युत वितरण कंपनियां घाटे से नहीं उबर पाई।

विद्युत वितरण कंपनियों पर इस समय 6.5 लाख करोड़ का कर्ज है। वितरण कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर हैं केंद्र सरकार बिजली वितरण कंपनियों को निजी क्षेत्र को सौंपने पर गंभीरता से विचार कर रही है। केंद्र सरकार देशभर की सभी बिजली कंपनियों की,वास्तविक आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट मंगाकर वित्तीय सेहत को देखते हुए निर्णय लेगी।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राज्यों में संचालित विद्युत वितरण कंपनियों को निजी क्षेत्र की कंपनियों को सौंपने पर विचार करने का निर्देश दिया है।

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दिया बड़ा संकेत

भारत में सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल

आरएनएस

नई दिल्ली। देश में लंबे समय से

लोगों की चली आ रही पेट्रोल-डीजल और गैस की कीमतों में कमी करने की मांग जल्द पूरी हो सकती है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्रकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि आने वाले समय में इन ईंधनों की कीमतों में कमी हो सकती है। उन्होंने बताया कि अमेरिका समेत अन्य देशों में तेल का उत्पादन बढाने की योजना बनाई जा रही है, जिससे वैश्विक बाजार में ईंधन की कीमतें घट सकती हैं और महंगाई पर भी काबू पाया जा सकता है।

मंत्री पुरी का कहना है कि अमेरिका में तेल उत्पादन बढाने के लिए पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना था ड्रिल, बेबी, ड्रिल यानी ज्यादा तेल निकालने का काम किया जाएगा। अब भी अमेरिका का उद्देश्य है कि अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों को घटाया जाए। उन्होंने बताया कि जब तेल और गैस का उत्पादन बढ़ेगा, तो इससे बाजार में तेल की आपूर्ति भी बढ़ेगी और कीमतों में कमी आ सकती है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि भारत का प्रमुख लक्ष्य यही है कि कम कीमतों पर पर्याप्त तेल की खरीदारी की जाए ताकि देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ कम किया जा सके।

पुरी ने यह भी स्पष्ट किया कि तेल की खरीदारी में डॉलर का इस्तेमाल खत्म करने का कभी कोई उद्देश्य नहीं था। उन्होंने कहा कि ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है और यह भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि भारत ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ संपर्क स्थापित किया है, और दोनों देशों के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में संबंध और मजबूत होंगे। पुरी ने कहा कि भारत अब 40 देशों से तेल आयात करता है। जिनमें अर्जेंटीना भी शामिल है। चूंकि अब दुनिया में तेल की पर्याप्त आपूर्ति है, तेल उत्पादक देशों को अपने उत्पादन को लेकर पुनर्विचार करना पड़ेगा, जिससे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में और कमी आ सकती है।

मेडिकल कॉलेजों को शीघ्र मिलेगी 156 नई फैकल्टी : डॉ. धन सिंह रावत

संवाद सहयोगी

देहरादून। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित मेडिकल कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसरों के रिक्त 156 पदों पर शीघ्र ही फैकल्टी तैनात कर दी जायेगी। जिससे राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों को फैकल्टी की कमी से काफी राहत मिलेगी।

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने आज बजट सत्र के बीच अपने कार्यालय कक्ष में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ राजकीय मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न संवर्ग के रिक्त पदों की समीक्षा की। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि चिकित्सा शिक्षा निदेशालय की ओर राज्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को मार्च 2024 में प्रोफेसरों एवं एसोसिएट प्रोफेसरों के रिक्त 153 पदों का अधियाचन भेजा था। जिस पर चयन प्रक्रिया अंतिम

चरण में है। इस दौरान विभागीय मंत्री ने सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष से वार्ता कर शीघ्र मेडिकल फैकल्टी उपलब्ध कराने को कहा। जिस पर बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा एक माह के भीतर फैकल्टी के चयन की सूची जारी करने की बात कही। डॉ. रावत ने बताया कि सेवा चयन बोर्ड से चयनित फैकल्टी की सूची मिलते ही शीघ्र विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में तैनाती कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से बोर्ड को भेजे गये अधियाचन में प्रोफेसरों के 53 तथा एसोसिएट प्रोफेसर के 103 पद शामिल है जिनमें एनेस्थीसिया, एनाटॉमी, बायोकैमिस्ट्री, बल्ड बैंक, कम्युनिटी मेडिसिन, डेंटिस्ट्री , डर्मेटोलॉजी, इमरजेन्सी मेडिसिन, फोरेन्सिक मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी, ऑब्स्टेट्रीक एंड गायनी, ऑप्थैलमोलॉजी, आर्थापेडिक्स, ओटो-राइनो-लेरिंगोलॉजी, पैथोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, फार्माकोलॉजी, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, फिजियोलॉजी, साईकाइट्री, रेडियोडायग्नोसिस, रेडियोथेरपी तथा रेस्पीरेट्री मेडिसिन विभाग के पद हैं। बैठक में मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के तहत हल्द्वानी, देहरादून और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में न्यूरो फिजिशियन तथा गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पद सृजित करने, पीजी की सीट बढ़ाने के लिये प्रस्ताव शासन को भेजन के निर्देश अधिकारियों को दिये गये। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पैरामेडिकल, टैक्नीशियन व अन्य नॉन मेडिकल पदों को भी शीघ्र भरने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं।

अच्छा काम करते-करते शराब की दुकान खोलकर राह से भटक गए केजरीवाल : अन्ना

ईएमएस

नई दिल्ली। सामाजिक कार्यकर्ता

अन्ना हजारे ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक मुख्यमंत्री के तौर पर अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने शराब की दुकानें खोलनी शुरू कर दी थीं और इसके परिणामस्वरूप उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। रेखा गुप्ता के दिल्ली की नई सीएम बनने पर हजारे ने कहा कि यह दिल्ली के लिए गर्व की बात है कि एक महिला शीर्ष कुर्सी पर बैठी है।

उन्होंने कहा कि लोगों ने रेखा गुप्ता को उनके शुद्ध विचारों और कार्यों के कारण वोट दिया है। अन्ना ने कहा कि सीएम के तौर पर केजरीवाल को समाज के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिए था, लेकिन वे अपनी राह से भटक गए। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को आम आदमी पार्टी के जन्म का श्रेय दिया जाता है। अन्ना हजारे ने आप सरकार की विवादास्पद आबकारी नीति का जिक्र करते हुए कहा कि पहले के केजरीवाल अच्छा काम कर रहे थे और तीन बार दिल्ली के सीएम बने। मैंने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा क्योंकि वह अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने धीरे-धीरे शराब की दुकानें खोलनी शुरू कर दीं और लाइसेंस जारी करने लगे। तब मैं परेशान हो गया।

कांग्रेस के वरिष्ठ और दिग्गज नेता ने राहुल गांधी से पूछा

पार्टी में मेरे लिए क्या काम? : थरूर

ईएमएस

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ

और दिग्गज नेता शशि थरूर अपनी ही पार्टी के नाराज बताए जा रहे हैं। थरूर के साथ हुई बातचीत के बावजूद, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनके किसी भी गिले-शिकवे या सुझावों पर कोई जवाब नहीं दिया। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस अब थरूर के प्रति नरम रुख अपनाने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि शशि थरूर ने राहुल गांधी से पार्टी में अपनी भूमिका को स्पष्ट करने का आग्रह किया था।

कांग्रेस थरूर से नाराज है क्योंकि उन्होंने पार्टी की नीति से हटकर कई मामलों पर अपनी राय दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से उनकी मुलाकात की उन्होंने सराहना की थी। इसके अलावा, केरल में एलडीएफ सरकार के द्वारा कि गए औद्योगिक विकास की सराहना करने वाले उनके लेख ने पार्टी में असंतोष पैदा कर दिया था। शशि थरूर ने राहुल गांधी से यह सवाल भी किया कि क्या पार्टी चाहती है कि वह राज्य राजनीति पर ध्यान केंद्रित करें, लेकिन राहुल ने इस पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। थरूर ने यह जानना चाहा कि अगर कांग्रेस का ऐसा इरादा है, तो उनकी भूमिका क्या होगी। इस पर राहुल ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस की परंपरा नहीं है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का चयन किया जाए।

थरूर इस बात से असंतुष्ट हैं कि बातचीत में राहुल की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। हालांकि, थरूर ने कांग्रेस के युवा विंग की जिम्मेदारी लेने के संकेत दिए थे, लेकिन राहुल इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। दिल्ली में कुछ दिन पहले हुई मुलाकात के दौरान थरूर ने पार्टी में खुद को नजरअंदाज किए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने इस पर कोई ठोस प्रतिबद्धता नहीं जताई, जिससे थरूर और भी असंतुष्ट हो गए।यह जानकारी भी सामने आई है कि थरूर पार्टी लाइन हटने का मन बना चुके हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है।

पीएम मोदी से मिलीं सीएम रेखा गुप्ता, लंबी चली बातचीत

ईएमएस

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद रेखा गुप्ता पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलीं हैं। यह मुलाकात करीब 1 घंटे 45 मिनट तक चली। बैठक के बाद ही सीएम रेखा पीएम आवास से बाहर

निकलीं। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद ही दिल्ली सरकार कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सक्रिय दिखी है, लेकिन अब इस मुलाकात के बाद एक्शन मोड साफ नजर आने वाला है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात से पहले रेखा गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर उनका हर एक दिन पूरी तरह से उपयोगी होना चाहिए। उन्होंने बताया कि शपथ लेते ही उनकी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक की, जिसमें केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को मंजूरी दी गई, जिसे पिछली सरकार लागू नहीं कर पाई थी।

पुल निर्माण तेजी से पूरा करने की मांग की

हरिद्वार। जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष गुलशन खत्री ने चंडीघाट पुल निर्माण की धीमी गति पर रोष जताया है। प्रैस को जारी बयान में गुलशन खत्री ने कहा कि हरिद्वार में मेलों के समय हाइवे पर लगने वाले जाम ओर चंडीघाट पुल पर ट्रैफिक के बढ़ते बोझ को देखते हुए देहरादून को कुमाऊं मंडल ओर लखनऊ से जोड़ने वाले चंडीघाट पुल के बराबर में नए पुल का निर्माण कार्य कुंभ से पहले 2020 में शुरू हुआ था और 2022 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन धीमीगति के कारण 2025 भी शुरू हो गया और लागत भी लगभग दोगुनी हो गई है। जिसकी वसूली भी जनता के पैसे से होगी। हाइवे अथॉरिटी के अधिकारी बार बार का 3/4 महीने काम पूरा होने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा वर्तमान में कांवड़ यात्रा के चलते पुराने पुल पर जाम की स्थित बनी हुई है। जिस कारण यात्रियों सहित स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बोर्ड परीक्षा शुरू होने के कारण परीक्षार्थियों को भी मानसिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने पुल निर्माण कार्य को तेजी से पूरा कराने की मांग की।

वहीं हरिद्वार-नजीबाबाद हाईवे पर शनिवार को कांवड़ियों की भीड़ उमड़ पड़ी। चंडी घाट पुल से चिड़ियापुर सीमा तक हाईवे का एक हिस्सा कांवड़ियों के हवाले कर दिया गया लेकिन चंडी पुल पर जाम लग गया। पुल के दोनों छोर पर तैनात पुलिस कर्मी यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करते नजर आए। हरिद्वार- नजीबाबाद मार्ग में कई जगहों पर लगातार जाम लगता रहा, इस वजह से पांच किलोमीटर की दूरी तय करने में वाहनों को एक घंटे से अधिक का समय लगा।

महानगर व्यापार मंडल की बैठक में बोले सुनील सेठी

भू कानून से हरिद्वार और उधम सिंह नगर को बाहर रखे जाने पर सीएम बधाई के पात्र

संवाद सहयोगी

हरिद्वार। सशक्त भू कानून लागू करने और हरिद्वार समेत उधमसिंह नगर को इससे बाहर रखने पर व्यापारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी है। महानगर व्यापार मंडल की महाराज विश्वास पूरी की अध्यक्षता में बैठक में मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुनील सेठी ने कहा कि व्यापार के स्तर से उद्यमियों के हित में ओर बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की हरिद्वार में आस्था को देखते हुए सरकार ने हरिद्वार को भू कानून से बाहर रखा है। हरिद्वार जिले में उद्यमियों के हिसाब से बड़े-बड़े प्रोजेक्ट चल रहे है और भविष्य के हिसाब से यहां ऐसे कार्य हो रहे है जिसका सीधा जुड़ाव व्यापारिक दृष्टिकोण से अन्य राज्यों से है। जिससे यहां के व्यापार को प्रगति मिलेगी। साथ ही इसी प्रकार उद्यमसिंह नगर को भी भू कानून से बाहर रखकर मुख्यमंत्री ने एक आर्थिक संतुलन बनाने का जो कार्य किया है। उसके लिए धामी सरकार बधाई की पात्र है। साथ ही उत्तराखंड की संस्कृति और हरित प्रदेश को बचाने के लिए जनता की लंबे समय से जो मांग राज्य में उठ रही थी। उस पर भू कानून लाकर अन्य राज्यों के लोगों की जमीन खरीद पर रोक लगाई वो भी स्वागतयोग्य है। प्रदेश के आर्थिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए एक अच्छा बेहतर भू कानून लाने पर महाराज विश्वास पूरी एवं खडखडेश्वर महादेव व्यापार मंडल अध्यक्ष भूदेव शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी सरकार बधाई की पात्र है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बधाई देने वालों में अरुण शर्मा, रवि बांगा, राकेश कुमार, राहुल तायल, रमन कुमार, अनिल कोरी, पवन पांडे, लक्की अनेजा, सुनील मनोचा, हरिओम शर्मा, सोनू चौधरी, पंकज माटा, महेश सिंह, दिनेश कुमार, रमेश, दलजीत, गजराज सिंह, महेश कालोनी, प्रीतकमल सारस्वत, धर्मपाल प्रजापति, विनेश शर्मा मौजूद रहे।

जीरो जोन में ई रिक्शा संचालन पर रोक और सड़कों से अतिक्रमण हटाया जाए

संवाद सहयोगी

हरिद्वार। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर कावंड मेला के दौरान जीरो जोन में ई-रिक्शा के संचालन पर रोक लगाने व सड़कों से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शिवभक्तों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नगर में नॉनवेज व शराब की दुकानों को बंद करवाया जाये।

ज्ञापन सौंपने के दौरान पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि महाशिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में शिवभक्तों के आने से शहर में भीड़ बढ़ रही है। मुख्य मार्गो पर आवागमन बाधित हो रहा है। जीरो जोन में ई-रिक्शा का संचालन होने और सड़कों पर अतिक्रमण कर लगायी गयी दुकानों से कठिनाई और अधिक बढ़ रही है। आये दिन शिवभक्तों व दुकानदारों के बीच कहासुनी हो रही है। ऐसी स्थिति में कभी भी बड़ा विवाद हो सकता है। इसलिए मुख्य मार्गो व जीरो जोन में यातायात को सुगम बनाने हेतु ई-रिक्शा को प्रतिबन्धित रखा जाये और मुख्य सड़को हाथी पुल, सुभाष घाट पुल व सीसीआर टावर के पास सड़कों पर अवैध अतिक्रमण कर लगी दुकानों को हटवाया जाये। उन्होंने कहा कि हर की पैडी क्षेत्र में तमाम नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ायी जा रही हैं। जिससे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने कहा कि शिवभक्तों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नगर में नॉनवेज व शराब की दुकानों को बंद करवाया जाये।

वरिष्ठ नागरिक संगठन ने की पूरे राज्य में एक समान भू कानून लागू करने की मांग

संवाद सहयोगी

हरिद्वार। वरिष्ठ नागरिक सामाजिक संगठन ने पूरे राज्य में एक समान भू कानून लागू करने की मांग की है। वरिष्ठ नागरिक सामाजिक संगठन के अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह ने बताया कि संगठन की ओर से राज्य में एक समान भू कानून लागू करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार को छोड़कर शेष 11 जिलों में नया भू कानून लागू करने का अध्यादेश पारित किया गया है। नए भू कानून से पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रो में क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलेगा जो राज्य की एकता अखंडता एवं समान विकास के सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं होगा। इससे सामाजिक और क्षेत्रीय विभाजन की समस्या आ सकती है और आपसी भाईचारा भी प्रभावित होगा। जो राज्य की एकता और अखंडता के लिए उचित नहीं है। निवेश और विकास कार्य प्रभावित होंगे। एक क्षेत्र के लिए सख्त कानून और उसी राज्य में हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए सामान्य कानून होने से आर्थिक असंतुलन बढ़ेगा और जनता को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह नीति समानता के सार्वभौमिक अधिकार के विरुद्ध है। जिससे कानूनी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि संगठन को आशा है कि सरकार नए भू कानून में संशोधन कर पूरे राज्य में एक जैसा संतुलित भू कानून लागू करेगी। पत्र भेजने वालों में चौधरी चरण सिंह, विद्यासागर गुप्ता, बाबूलाल सुमन, हरदयाल अरोड़ा, सुखबीर सिंह, श्याम सिंह, ताराचंद, रामसागर, शिवचरण, सुभाषचंद्र ग्रोवर, शिवकुमार शर्मा आदि वरिष्ठ नागरिक शामिल रहे।

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने किया नवनियुक्त ईदगाह कमेटी का स्वागत

संवाद सहयोगी

हरिद्वार। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने ईदगाह कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष जमशेद खान एवं उनकी टीम का स्वागत किया। जमशेद खान के आर्यनगर चौक स्थित कार्यालय पर स्वागत के दौरान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि नवगठित टीम समाज को संगठित कर समाज हित में कार्य करे। एकता सौहार्द को बढ़ावा दें। ईदगाह कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष जमशेद खान व सेक्रेटरी बाबर खान ने कहा कि पूरी ईमानदारी, कर्मठता से समाज हित में काम किया जाएगा। ईदगाह के रखरखाव एवं सौंदर्यकरण के कार्यों को बढ़ चढ़कर किया जाएगा। ईदगाह में नमाजियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। साफ सफाई के भी विशेष इंतजाम किए जाएंगे। कमेटी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर सामाजिक दायित्व को निभाया जाएगा। शाहनवाज अब्बासी ने ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष जमशेद खान एवं उनकी टीम का स्वागत करते हुए कहा कि नवनियुक्त टीम ईदगाह के विकास में निर्णायक भूमिका निभाएगी। नमाजियों को किसी भी प्रकार की और असुविधा नहीं होगी। समस्याओं एवं लोगों की शिकायतें दूर करने में पूरी टीम सक्षम है। उन्होंने वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स का आभार जताया। नवनियुक्त ईदगाह कमेटी में उपाध्यक्ष सज्जाद गॉड, कोषाध्यक्ष हाजी मुकर्रम अली, सदस्य एहसान अंसारी, हाजी अब्बास अब्बासी, नसीम सलमानी, सैफुल्लाह कुरैशी, नाजिम कुरैशी, मीरा, शहनवाज सिद्दीकी, नौशाद मंसूरी शामिल हैं। इस दौरान शौकीन अब्बासी, सिराजुद्दीन, जमीन अहमद, मोनू अब्बासी, नदीम पीरजी, आकिब मंसूरी, रहमान अंसारी, यासीन अंसारी, परवेज गौड मौजूद रहे।

वहीं नगर निगम ने डोर टू डोर उठने वाले कूड़े को एकत्रित करने के लिए अपनी भूमि की तलाश शुरू कर दी है। अभी तक निगम के कर्मचारी फुटबॉल ग्राउंड से सटी खाली पड़ी भूमि में कूड़ा करकट एकत्र कर रहा है। क्योंकि डोर टू डोर उठने वाले कूड़े को एक स्थान पर एकत्रित कर बड़े वाहनों से सराय स्थित डंपिंग जोन में भेजा जाता है। निगम भूमि मिलने तक खाली पड़ी विवादित भूमि पर सफाई कर्मचारियों की अतिरिक्त ड्यूटी लगाएगा।

शांतिकुंज आए रशियन दल को किया सम्मानित

संवाद सहयोगी

हरिद्वार। रूस के मास्को से एक दस सदस्यीय युवाओं का दल शांतिकुंज पहुंचा। दल में उच्च प्रशिक्षित व आईटी प्रोफेशनल्स शामिल हैं। महाकुंभ प्रयागराज में स्नान के बाद गायत्री तीर्थ पहुंचे दल ने गायत्री महायज्ञ एवं साधना में भाग लिया। शांतिकुंज प्रवास के दौरान रशियन दल ने देवसंस्कृति विवि के प्रतिकुलपति डा.चिन्मय पण्ड्या से भेंट की और गायत्री साधना, उपासना से संबंधित अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाया। डा.चिन्मय पण्डया ने साधना से सिद्धि सहित विभिन्न विषयों पर रशियन दल का मार्गदर्शन किया और सभी को पं.श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा रचित युग साहित्य भेंट कर सम्मानित किया।

गौरतलब है कि अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख डा. प्रणव पण्ड्या एवं देवसंस्कृति विवि के प्रतिकुलपति डा.चिन्मय पण्ड्या ने रूस यात्रा के दौरान उन्हें शांतिकुंज आने का आमंत्रण दिया था। शांतिकुंज विदेश विभाग ने बताया कि इससे पहले भी रशियन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका सहित विभिन्न देशों के साधक गायत्री साधना करने शांतिकुंज आते रहे हैं। शांतिकुंज का वातावरण साधकों को मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक विकास की दिशा में बहुत सहायता प्रदान करता है।

गुरुकुल कांगड़ी विवि में आयोजित सेमिनार में बोली प्रो. हेमलता

बदलते मौसम, खानपान व दिनचर्या से उत्पन्न हो रही है ब्याधियां

संवाद सहयोगी

हरिद्वार। गुरुकुल कांगड़ी विवि में सेमिनार में मुख्य अतिथि विवि कुलपति प्रो. हेमलता ने कहा कि बदलते मौसम, खानपान और दिनचर्या से हर रोज नई व्याधियां पैदा हो रही हैं। यह व्याधियां समाज के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही हैं। कुलपति ने कहा कि व्याधियों से बचाव के लिए अपनी दैनिक जीवन शैली को अनुशासन में ढालकर शुद्ध खान-पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने प्रतिभागियों से कहा कि फार्मा क्षेत्र में अनुसन्धान एवं नवाचार के लिए अपार सम्भावनाएं हैं। अत: सभी को अपने विषय के ज्ञान में दक्षता हासिल कर अपने भविष्य को स्वर्णिम बनाना चाहिए।

वहीं देवभूमि भैरव सेना संगठन के चरणजीत पाहवा ने सिटी मजिस्ट्रेट नगर स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन देकर महाशिवरात्रि पर्व और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर नगर निगम क्षेत्र में मांस व अंडे की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। चरणजीत पाहवा ने कहा कि महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर होने वाली कावड़ यात्रा चरम पर है। लगातार श्रद्धालु कांवड़ लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इसलिए धर्मनगरी की मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए 24 से 26 फरवरी क्षेत्र में मांस अंडे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।

कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र की टिप्पणी के विरोध में कांग्रेसियों ने फूंका पुतला

संवाद सहयोगी

हरिद्वार। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा विधानसभा में उत्तराखंड वासियों के लिए अमर्यादित टिप्पणी करने के विरोध में जिला महानगर कांग्रेस कमेटी ने देवपुरा चौक पर प्रदर्शन कर सरकार का पुतला फूंका।

महानगर कांग्रेस अध्यक्ष अमन गर्ग और युवा नेता वरुण बालियान ने कहा कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा विधानसभा सदन में पर्वतीय समाज को लेकर की गयी अमर्यादित टिप्पणी से उत्तराखंड की शहादत व वीरांगनाओं का अपमान हुआ है। यदि जल्द से जल्द मंत्री का इस्तीफा नहीं होता तो उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। पूर्व पार्षद राजीव भार्गव और कैलाश भट्ट ने कहा कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा की गयी वैमनस्य पैदा करने वाली टिप्पणी से सम्पूर्ण उत्तराखंड वासी आहत हैं। महानगर कांग्रेस महासचिव तरूण व्यास और युवा नेता अजय गिरी ने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा विधानसभा सदन में जिन शब्दों का प्रयोग किया। उसकी सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। उन्हें तुरंत उत्तराखंड वासियों से माफी मांगनी चाहिए। पार्षद हिमांशु गुप्ता और ब्लाक अध्यक्ष विकास चंद्रा ने कहा कि भाजपा षड्यंत्र के तहत उत्तराखंड में क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। जिसे उत्तराखंडवासी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्षद सोहित सेठी और वरिष्ठ नेता बलराम गिरी कड़क ने कहा कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा विधानसभा सदन में की गई टिप्पणी पर यदि भाजपा द्वारा कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पार्षद प्रतिनिधि शहाबुद्दीन अंसारी और वरिष्ठ नेता मनोज सैनी ने कहा कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की टिप्पणी से देवभूमि उत्तराखंड का अपमान हुआ है और साथ ही उन लोगों की भावनाएं भी आहत हुई हैं और राज्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों का अपमान हुआ है। प्रदर्शन और पुतला दहन में मुख्य रूप से श्रमिक नेता विकास सिंह, मोहनलाल राणा, सेवादल अध्यक्ष अश्विन कौशिक, दीपक पाण्डेय, अवधेश कुमार, पूर्व पार्षद उदयवीर सिंह, कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश वालिया, हिमांशु राजपूत, पार्षद प्रतिनिधि इदरीस मंसूरी, वार्ड अध्यक्ष केशव काम्बोज, नागेश रावत, योगेश पाण्डेय, रोहित सिंह आदि शामिल रहे।

अज्ञात चोरों ने कपड़े की दुकान से लाखों का कपड़ा उड़ाया

संवाद सहयोगी

हरिद्वार। धनपुरा में कपड़े की एक दुकान को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। चोर कीमती कपड़ा लेकर चंपत हो गए। मामले में पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस जांच में जुटी। ग्राम धनपुरा निवासी डॉक्टर अब्दुल समन्ध ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उसके बेटे की धनपुरा गांव में ही कपड़े की दुकान है। बीती रात अज्ञात चोरों ने दुकान को अपना निशाना बना लिया और दुकान से लाखों का कीमती कपड़ा लेकर फरार हो गए। सुबह जब दुकान खोलने के लिये उनका बेटा दुकान पर पंहुचा तो दुकान का टूटा ताला देख उसके होश उड़ गए। दुकान से लाखों का कीमती कपड़ा गायब है। मामले में पीड़ित ने पुलिस को अज्ञात चोर के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फेरुपुर चौकी प्रभारी सुधांशु कौशिक ने बताया चोरी की तहरीर आई है मामले की जांच की जा रही है। वहींबिना बताए घर से चले आए एक किशोर को मानव तस्करी निरोधक दस्ते ने परिजन को सौंप दिया। परिजन बार बार पुलिस का शुक्रिया अदा करते रहे। दस्ते के प्रभारी निरीक्षक विजय सिंह ने बताया कि बीस फरवरी को टीम को एक बालक लावारिसवस्था में घूमते हुए मिला था। बताया कि 12 वर्षीय बालक को बाल कल्याण समिति के खुला आश्रम गृह कनखल में दाखिल कराया गया था। उसने एक मोबाइल फोन नंबर उपलब्ध कराया था, जिसके बाद टीम ने उस मोबाइल फोन नंबर पर संपर्क साधा। बताया कि सूचना मिलने पर उसके पिता नरेंद्र शर्मा और बुआ सीमा शर्मा निवासी ग्राम डोला थाना सिंघावली अहीर जिला बागपत यूपी यहां पहुंच गए, जिनके सुपुर्द उस बालक को किया गया।

वहीं दूसरी ओर पिछले साल लापता तीन कांवड़ियों का पता नहीं चलने पर पुलिस ने उनकी गुमशुदगी को अपहरण में तरमीम कर लिया है। पुलिस ने फिर से तीनों की तलाश शुरू कर दी है। नैनीताल जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के हल्दुआ निवासी मधु देवी पत्नी राजेंद्र सिंह ने पुलिस को बताया था कि उसका बेटा राहुल पांच अगस्त को डाक कांवड़ लेकर यहां आया था। वह चमगादड़ टापू पार्किंग में अपनी बाइक पार्क कर चला गया था लेकिन वापस लौटकर नहीं आया।

चोरी का विरोध करने पर मकान मालिक पर हमला करने वाला गिरफ्तार

रुड़की। घर में घुसकर चोरी करने और मकान मालिक को घायल करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से छह हजार रुपए की नगदी और लोहे की रॉड बरामद हुई। पुलिस एक अन्य फरार आरोपी की तलाश में संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है। शुक्रवार रात को मानक मजरा गांव के एक घर में दो लोग घुस गए थे। वह दोनों घर में रखी नगदी और अन्य कीमती सामान चोरी कर रहें थें। इस दौरान पास में सो रहे मकान मालिक की आंख खुल गई। उसने दोनों चोरों को रोकना चाहा तो आरोपियों ने लोहे की रॉड से उसके सर पर हमला कर दिया। जिससे वह घायल होकर जमीन पर गिर गया। प्राथमिक उपचार के बाद मकान स्वामी मिंटू ने तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। जिसके आधार पर मिले महत्वपूर्ण सुराग के आधार पर पुलिस ने सोलानी नदी पुल के पास से एक युवक को गिरफ्तार कर लिया।

अंकित हत्याकांड मामले का पुलिस ने किया खुलासा

बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए कातिल बना पिता

नागरिक ब्यूरो

रुड़की। अंकित हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुख्य षडयंत्रकर्ता सहित 03 हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया है। बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए आरोपी ने अंकित की हत्या की सुपारी 04 लाख रुपये में दी थी जिसका एडवांस चार हजार रुपए दिया गया था।खुलासे पर आईजी रेंज द्वारा 15000 रुपए व एसएसपी हरिद्वार द्वारा टीम के लिए 5000 रुपए के ईनाम की घोषणा की गई है। बीती 20 फरवरी को ग्राम झबीरण जट स्थित शमशान घाट के पास 26 वर्षीय अंकित पुत्र सहंसरपाल का शव मिला था। मृतक अंकित को पूर्व में कपिल हत्याकांड में कोतवाली मंगलौर पुलिस द्वारा जेल भेजा गया था जो कुछ समय पहले ही जमानत पर छूटा था। शव मिलने की सूचना पर एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल हत्या की संभावना के दृष्टिगत एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल, सीओ मंगलौर विवेक कुमार आदि संग मौके पर पहुंचे। फील्ड यूनिट हरिद्वार द्वारा घटनास्थल से भौतिक/ वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किए। ग्रामीण क्षेत्र में चाकू गोंदकर की गई इस हत्या को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी डोबाल द्वारा कोतवाली स्तर पर पुलिस टीम का गठन कर टैक्निकल सपोर्ट के लिए सीआईयू रुड़की को नियुक्त किया तथा पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सीओ मंगलौर विवेक कुमार को देते हुए जल्द से जल्द घटना का सफल अनावरण करते हुए वारदात में शामिल सभी किरदारों को गिरफ्तार करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए। गठित की गई पुलिस टीम के कुछ सदस्यों को स्थानीय मुखबिरों के साथ मिलकर सटीक इनपुट खोजने पर जबकी अन्य सदस्यों को घटनास्थल के इर्द-गिर्द से डिजीटल एविडेंस इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई। कुछ समय पहले ही हत्या के मामले में जमानत पर छूटे मृतक का बैकग्राउंड जांचने एवं जुटाए गए सबूतों को कड़ी दर कड़ी जोड़ने पर सामने आए कुछ संदिग्ध चरित्रों को पकड़ने के लिए लगातार ताबड़तोड़ दबिशे देकर मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने संजय सैनी, दीपांशु व विकास कुमार उर्फ विक्की को दबोचकर उनके कब्जे से कत्ल में इस्तेमाल चाकू बरामद किया गया। आरोपी कपिल हत्याकांड में जेल जा चुका था तो मृतक अंकित के ग्राम कुरडी स्थित अपने घर के सामने से गुजरने पर मृतक कपिल के पिता संजय सैनी के मन में खुद बदला लेने की आग प्रतिदिन बढ़ती रही। संजय सैनी ने दीपांशु, विकास, अमन व रोहित नाम के युवकों से चार लाख रुपए में अंकित कुमार की हत्या का सौदा तय किया तथा चार हजार बतौर एडवांस दिए। तय योजना के मुताबिक आरोपी युवकों ने पहले मृतक अंकित कुमार को नशा कराया और फिर उसके बाद चाकू से अंकित के शरीर पर ताबड़तोड़ वार किए। इसके बाद अंकित को मरा हुआ समझकर आरोपित मौके से फरार हो गए। हत्यारोपी विकास का पूर्व में भी चोरी, लूट व गैंगस्टर आदि के मुकदमों में आरोपी रहा है। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक शान्ति कुमार, वरिष्ठ उप निरीक्षक रफत अली,उप निरीक्षक मुनब्बर हुसैन, संजीव चौहान, ध्वजवीर सिह, नवीन चौहान, नीरज रावत, मनोज कठैत, राकेश डिमरी, बीरपाल, योगेन्द्र सिह, गजपाल राम, माजिद, श्याम बाबू, मोहन, और राहुल शामिल रहे।

दो महिला समेत सात आरोपियों के खिलाफ अवैध कटान का मुकदमा दर्ज

रुड़की। मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि कुछ लोग खटका बाईपास के पास अवैध कटान कर रहें है। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर कटान कर रहे आरोपी इधर उधर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से 250 किलो प्रतिबंधित मांस, एक बाइक और कटान के उपकरण आदि बरामद किए। पुलिस पकड़े गए आरोपी जावेद निवासी जबरदस्तपुर कोतवाली रुड़की को कोर्ट में पेश करने के साथ ही फरार आरोपी अमजद, परवेज, इमरान, नवाजिस, अंजुम, बुसरा की तलाश में संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है। कोतवाली प्रभारी कुश मिश्रा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फरार आरोपियों की तलाश में संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है।

मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान से गुस्से में पहाड़ी समाज, फूंका पुतला

नागरिक ब्यूरो

रुड़की। विधानसभा में केबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ी समाज के लिए की गई टिप्पणी के विरोध में शनिवार को उत्तराखंड एकता मंच के बैनर तले पहाड़ी मूल के लोगों ने प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कैबिनेट मंत्री पद से बर्खास्तगी की मांग की।

सुभाष नगर में गढ़वाल धर्मशाला के समीप उत्तराखंड एकता मंच कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन के दौरान मंच के कॉर्डिनेटर प्रवेश जोशी ने कहा ऐतिहासिक एवं सरकारी दस्तावेजों से यह प्रमाणित है कि गढ़वाली, कुमाऊनी और अन्य पहाड़ी समुदाय उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और वे सदियों से यहां निवास कर रहे हैं। यदि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पास कोई आधिकारिक प्रमाण हैं, जो यह दर्शाते हों कि उत्तराखंड के मूल निवासी बाहरी हैं, तो उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया जाए। अन्यथा, उन्हें अपने भ्रामक एवं अपमानजनक बयान के लिए न केवल लिखित रूप में, बल्कि विधानसभा के भीतर भी सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करनी चाहिए। टी आर भट्ट ने कहा राज्य के निर्माण में गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार आदि सभी क्षेत्रों के लोगों ने अपने-अपने स्तर से भागीदारी की है, जिससे यह राज्य अस्तित्व में आया।किसी भी व्यक्ति द्वारा इन पर अमर्यादित टिप्पणी किया जाना न केवल निंदनीय है, बल्कि असहनीय भी है। पंकज मैंदोला ने कहा भाजपा सरकार के संसदीय कार्य, शहरी विकास एवं वित्त मंत्री एवं ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा विधानसभा सदन में पहाड़ियों के लिए अमर्यादित और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जो कि उत्तराखंड की अस्मिता का अपमान है। हमारी मांग है कि विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पर कठोर कार्रवाई करें एवं धामी सरकार उन्हें तत्काल मंत्री पद से निष्कासित करें। विरोध प्रदर्शन करने वालों में उत्तराखंड एकता मंच के कार्यकर्ता प्रवेश जोशी, सुनील रौथाण, राजेश चमोली, विजय रावत, अनिल उप्रेती, दीपक नैथानी, विजेंद्र सेमवाल, दीपक रावत, किरण जोशी, रंजना रावत, सीमा रावत, पूजा शर्मा, रविता पटवाल, सुभागा रौथाण, रोहन रौथाण, अनिमेष जुयाल, मानवी रावत, अंकिता रौथाण, प्रभाकर बडोला व आदि सम्मिलित थे।

महिला उद्यमिता एवं कौशल विकास पर संगोष्ठी का आयोजन

नागरिक ब्यूरो

रुड़की। राजकीय महाविद्यालय मे शनिवार को अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत महिला उद्यमिता एवं कौशल विकास सशक्त भारत के आर्थिक विकास का आधार विषयक दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया। संगोष्ठी भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा आयोजित की गई। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के मानविकी संकाय के अर्थशास्त्र विभाग के डॉ० विपुल भट्ट मुख्य वक्ता रहें। कार्यक्रम की पहले सत्र की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. प्रेमलता द्वारा की गई। दीप प्रज्वलन और ईश वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। संगोष्ठी की संयोजिका राजकीय महाविद्यालय मंगलौर की अर्थशास्त्र विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ रचना वत्स और आयोजन सचिव राजनीति विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ तीर्थ प्रकाश रहें। संगोष्ठी के अन्य विशिष्ट वक्ता बीएसएम पीजी कॉलेज के अर्थशास्त्र विभाग के डॉ सुरजीत सिंह और वर्धमान कॉलेज बिजनौर के डॉ चारू दत्त आर्य रहें। कार्यक्रम का मंच संचालन डॉ तीर्थ प्रकाश ने किया। कार्यक्रम शुरुआत में डॉ० रचना वत्स ने कार्यकम की रुपरेखा प्रस्तुत की। इसके बाद विशेष और मुख्य वक्ताओं द्वारा अपना उद्बोधन दिया। मुख्य वक्ता डॉ० विपुल भट्ट ने अपने व्याख्यान में कहा कि आधी आबादी को ध्यान में रखे बिना भारत सरकार की कोई योजना सफल नहीं हो सकती। तकनीक सत्र की अध्यक्षता राजकीय महाविद्यालय कोटद्वार से आए विशेष अतिथि डॉ अनुराग शर्मा द्वारा की गई। इस तकनीकी सत्र में डॉ मेघा जुयाल, डॉ प्रज्ञा राजवंशी, डॉ आबिदा, डॉ मीना नेगी ने अपने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए और साथ ही डॉ अंशु पांडे और डॉ गोरखनाथ के शोध पत्र का वाचन महाविद्यालय के छात्राओं अना और मेहरबा द्वारा किया गया। तकनीकी सत्र का समापन डॉ अनुराग शर्मा के भाषण से हुआ। उन्होंने समस्त शोध पत्र वाचनकर्ताओं को बधाई प्रेषित करते हुए कहा कि अपनी परम्परागत कार्यों को कोशल विकास से जोड़कर आज सीखने की जरूरत है। उन्होंने कई उदाहरणों के माध्यम से समझाया कि आज देश को महिला उद्यमिता की महती आवश्यकता है। संगोष्ठी की संयोजिका और आयोजन सचिव द्वारा अंत में समस्त अतिथियों को शाल और स्मृति चिह्न भेंट कर उनका आभार किया गया।

शमशान घाट में अस्थियों के साथ छेड़छाड़ करने व तंत्र विद्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार

नागरिक ब्यूरो

रुड़की। शमशान घाट में अस्थियों के साथ छेड़छाड़ करने और तंत्र विद्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।

कलियर थाना पुलिस को मेहवड़ कला निवासी आयुष्मान पराशर ने तहरीर देकर बताया था कि श्मशान घाट में उनके स्वर्गीय नाना के मृत शरीर जिनका अन्तिम संस्कार 20 फरवरी को हुआ था जिनके बचें अवशेषों अस्थियों के साथ छेड़छाड़ व अंत्येष्टि संस्कारों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम एक युवक द्वारा किया गया था। ग्राम वासियों द्वारा आरोपी साबिर मलिक को शमशान घाट मेहवड़ कला के पास से मय तांत्रिक विद्या से संबंधित सामग्री के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। पुलिस ने साबिर मलिक पुत्र इस्लाम अहमद निवासी मोहल्ला सती को न्यायालय में पेश किया है।

वहीं ऊर्जा निगम ने बकाया जमा नहीं करने पर तेल्लीवाला गांव में कुछ लोगों के कनेक्शन काट दिए। इस गांव में रात में टीम दोबारा चेकिंग करने पहुंची तो कनेक्शन कटने के बाद कुछ उपभोक्ता कटिया डालकर बिजली चोरी कर रहे थे। टीम ने मौके पर ही छापा मारकर उन्हें बिजली चोरी के मामले में भी पकड़ लिया। अब उपभोक्ताओं पर बकाया जमा नहीं करने और बिजली चोरी करने के मामले में कार्रवाई होगी।

एक्ट में संशोधन के विरोध में सड़कों पर उतरे अधिवक्ता

नागरिक ब्यूरो

रुड़की। एडवोकेट एक्ट में संशोधन के विरोध में शनिवार को अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा इसके साथ ही पूरे दिन कार्य बहिष्कार पर रहे।

रुड़की में अधिवक्ताओं ने एडवोकेट एक्ट में संशोधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से इसे वापस लिए जाने की मांग की। रामनगर स्थित कोर्ट परिसर से जुलूस निकाला जो कि रामनगर कोर्ट परिसर से शुरू होकर आजाद नगर चौक, बीएसएम तिराहा, गणेशपुर पुल,गोल चौक होते तहसील पहुंचा। जहां ज्वाइंट मस्जिट्रेट आशीष कुमार मिश्रा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। जिसमें उन्होने एडवोकेट एक्ट 1961 मे संशोधन हेतु लाये गये अमेटमेण्ट बिल 2025 के प्रस्तावित प्राविधानों के अधिवक्ता एवं अधिवक्ताओं की मातृ संस्था स्टेट बार काउसिंल्स के अधिकारो के हनन का विरोध किया। शनिवार को दिए ज्ञापन में कहा कि भारत सरकार द्वारा एडवोकेट एक्ट 1961 मे संशोधन हेतु लाये गये अमेटमेण्ट बिल 2025 के प्रस्तावित प्राविधानों के अधिवक्ता एवं अधिवक्ताओं की मातृ संस्था स्टेट बार काउसिंल्स के अधिकारो के हनन के विरोध में अधिवक्ताओं ने आपात कालीन सभा आहूत की गयी। अधिवक्ताओं के सुझाव लेने के उपरान्त बार एसोसिऐशन ने एडवोकेट एक्ट में प्रस्तावित संशोधनों का पुरजोर तरीके से विरोध किये जाने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त विधि मन्त्रालय की ओर से जारी किये गये ई-मेल नम्बरो पर सभी अधिवक्तागण की ओर से विरोध में मैसेज कराये जाने के साथ-साथ शनिवार को न्यायिक कार्य से विरत रहे। एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी लिल्लू सिंह और सचिव राजीव चौधरी ने कहा कि बार काउंसिल के आह्वान पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। कहा कि आवश्यकता हुई तो आगे भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर बार कौंसिल उत्तराखंड सदस्य राव मुनफैत अली, एडवोकेट अतुल शर्मा,पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोमर,पूर्व सचिव अनित चौधरी,शिव कुमार सैनी,राव नावेद,नवीन जैन, नरोत्तम त्यागी, शीतल कालरा,संदीप यादव, श्रीगोपाल नारसन,राव बिलावर, मोहम्मद मुबशशीर,बिलाल अहमद, राव परवेज, फरमान त्यागी, विपीन पहलवान,सत्तो बर्मन, सिमा, खुशी,रवि जैन, मुरसलीन,अबुलीन,बिजेपाल पुण्डीर, राजकुमार,नवीन शर्मा एंड,रवि मोहन कौंसिल, कल्याण सिंह, चौधरी अजित,अजय शर्मा मीरा, सोनी सिंह, अनुराधा,मनोज चौधरी, सुखपाल सिंह, राव साजिद आदि शामिल रहे।

वार्ड नंबर 16 में हुआ आयोजित हुआ सम्मान समारोह

मेयर अनीता ललित अग्रवाल का स्वागत

नागरिक ब्यूरो

रुड़की। प्रथम महिला मेयर अनीता ललित अग्रवाल का स्वागत वार्ड नंबर 16 में ऋषिपाल सिंह चौहान पूर्व तहसीलदार के आवास पर रुड़की की प्रथम महिला मेयर अनीता देवी अग्रवाल का स्वागत समारोह किया गया इस अवसर पर ललित मोहन अग्रवाल पी डब्लू ओ के अध्यक्ष कुलदीप अग्रवाल, रिशिपाल चौहान, ज्ञान शर्मा , उषा गुप्ता, मदनपाल कंबोज मास्टर सतेंद्र सिंह वार्ड नंबर 16 के पार्षद अंकित चौधरी, अरविंद ,ऋषिपाल , रवि ,शंकर शर्मा, अमित शर्मा ,नवीन ,प्रवीण शर्मा, पुनीत राजपूत, दिव्यांशी यादव, शीतल शर्मा , पूनम व नितिन चौहान द्वारा अनीता को सॉल पहनकर स्वागत किया गया। ऋषिपाल द्वारा ललित अग्रवाल को सॉल पहनाकर स्वागत किया गया आर्य समाज के मंत्री संदीप यादव महर्षि दयानंद जी के 201 में जन्म दिवस के उपलक्ष में सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक से प्रेम भेंट की अनीता ललित अग्रवाल ने आश्वासन दिया कि वह रूड़की को बहुत ही सुंदर स्वच्छ बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्दी सभी योजना आपको क्रियान्वयन होते हुए दिखाई देंगे कार्यक्रम का संचालन आर्य संदीप यादव एडवोकेट मंत्री आर्य समाज रामनगर के द्वारा किया गया।

केजरीवाल को दिया चैलेंज का जवाब : निशंक

नागरिक ब्यूरो

रुड़की। 2010 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुझे चैलेंज दिया था अब पार्टी ने मौका दिया तो केजरीवाल को उसका जवाब दिया गया है। उक्त बात निशंक ने रुड़की में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कही। निशंक को दिल्ली चुनाव में पांच सीटों की जिम्मेदारी मिली थी सभी सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। सुभाष नगर में भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिला मंत्री मनोज तोमर के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक का रुड़की पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर भरोसा किया है और पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर सरकार बनवाई है। उन्होंने कहा कि 2010 में जब वह मुख्यमंत्री थे तो उत्तराखंड आए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल उन्हें मैदानी क्षेत्र में चुनाव लड़ने की चेतावनी दी थी उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में पांच सीटों की जिम्मेदारी दी जो कि वह जिताकर आए हैं। वहीं उन्होंने बजट सत्र और भू कानून पर मुख्यमंत्री धामी की सराहना की। कार्यक्रम संयोजक मनोज तोमर ने पटका पहना कर उनका स्वागत किया एवं पूरे परिवार ने फूल मालाओं से निशंक का स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति, महामंत्री अरविंद गौतम,कविंद्र चौधरी, नीरज तोमर,अनुज तोमर,उदयवीर सिंह,गीता सिंह,रवि राणा, मंजू सिंह,विपुल,नेहा पंवार राजकुमार, मोनिका, मोनिका चौधरी, प्रथम, अभयजीत,आर्यन अरनव,अहम तोमर,सविता संगीता,कुंवरपाल प्रधान,राजेंद्र सैनी, सूरज नेगी, चंदन त्यागी,रामगोपाल कंसल, राकेश उपाध्याय आदि शामिल रहे।

व्यक्ति ही नहीं परिवार और समाज का विनाश करता है नशा

संवाद सहयोगी

बागेश्वर। जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति का ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज का विनाश कर देता है। इसके कारण युवा अपनी शिक्षा, कॅरियर और पारिवारिक रिश्तों से दूर हो जाते हैं, जिससे सामाजिक ताना-बाना कमजोर हो जाता है। युवा पीढ़ी को इसकी गर्त में जाने से बचाने की जरूरत है। इसके लिए जिले में नशामुक्ति अभियान चलाएं।

यह निर्देश उन्होंने शुक्रवार को आयोजित नशामुक्ति कार्यक्रमों की प्रगति समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने शिक्षा संस्थानों, महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निक प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए। शैक्षणिक संस्थानों में व्यापक स्तर पर नशा मुक्ति अभियान चलाएं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक युवाओं तक यह संदेश पहुंचे। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि नशा मुक्ति को थीम बनाकर एक 'युवा महोत्सव आयोजित करें, जिसमें निबंध लेखन, रंगोली, मेहंदी, पोस्टर मेकिंग, फैशन वॉक जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को नशा मुक्त जीवन की ओर प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि जब युवा खुद अपनी सोच से नशे के खिलाफ खड़े होंगे, तभी यह अभियान सफल होगा।

उन्होंने सभी सदस्यों को निर्देश दिया कि वे इस अभियान को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। नशे को न कहें, जीवन को हां कहें। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. कुमार आदित्य तिवारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी जसमीत कौर मौजूद रहे।

एनआईटी श्रीनगर में मनाया गया विश्व सामाजिक न्याय दिवस

श्रीनगर गढ़वाल। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल के निर्देशानुसार सिविल जज अलका की अध्यक्षता में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। एनआईटी श्रीनगर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सिविल जज अलका ने कहा कि सामाजिक न्याय की मांग यही है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। इसके लिए हमें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना जरुरी है। इस मौके पर विमल शर्मा, बार एसोसिएशन श्रीनगर के संरक्षक अनूप श्री पांथरी, बार एसोशिएशन अध्यक्ष प्रमेश चन्द्र जोशी, पूनम हटवाल मानव विष्ट, प्रियंका राय, प्रकाश नेगी, महिला थानाध्यक्ष संध्या नेगी आदि मौजूद थे

श्रीनगर में छात्रों और कांग्रेसियों का प्रदर्शन

श्रीनगर गढ़वाल। विधानसभा सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर पहाड़ी समाज के लोगों को अपशब्द कहने का आरोप लगाते हुए शनिवार को श्रीनगर के छात्र संगठन सहित कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों और छात्र नेताओं ने गोला पार्क व विवि गेट पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्र नेताओं और कांग्रेसियों ने सरकार से कैबिनेट मंत्री को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग उठाई। कांग्रेस नगर अध्यक्ष सूरज घिल्डियाल, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस डा. प्रताप भंडारी, पार्षद सूरज नेगी, जय हो छात्र संगठन के विरेंद्र बिष्ट ने कहा कि कैबिनेट मंत्री द्वारा पहाड़ी समाज के लोगों के लिए अपशब्द का प्रयोग किया जाना देवभूमि के लोगों का अपमान है। कहा कि मंत्री द्वारा कैबिनेट की गरिमा का ख्याल भी नहीं रखा गया। आक्रोशित लोगों ने मुख्यमंत्री से तत्काल कैबिनेट मंत्री को पद से बर्खास्त किए जाने की मांग की है। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस प्रताप सिंह भंडारी, पार्षद सूरज नेगी, संजय कुमार, सुरेंद्र सिंह चौहान, प्रीति, जगदीश भट्ट, आंचल राणा, निशांत कंडारी, छात्र नेता शुभम पंवार, मनोज, काजल शुक्ला, शालिनी, वर्षा, आय शा,राहुल तनुज आदि छात्र मौजूद थे।

चार साल बाद हत्या के आरोपी पति-पत्नी गिरफ्तार

संवाद सहयोगी

पिथौरागढ़। दिसंबर 2021 में बस्ते में एक व्यक्ति की हत्या मामले में फरार चल रहे पति-पत्नी को पुलिस ने बहराईच से गिरफ्तार किया है। कानूनी प्रक्रिया के बाद दोनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक 6 दिसंबर 2021 से बस्ते निवासी ओमप्रकाश गुमशुदा चल रहा था। 8 दिसंबर को धनौड़ा हरीश चन्द्र ने जाजरदेवल पुलिस को जानकारी दी कि सनराईज स्कूल बस्ते जाने वाली रास्ते में एक पुराने कमरे के भीतर शव पड़ा हुआ है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव की ओमप्रकाश के रुप में शिनाख्त की। ओमप्रकाश के गुप्तांगों को काट दिया गया था और आंख व शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी धारा 302 में मुकदमा पंजीकृत किया। पुलिस को विवेचना के दौरान हत्या में शामिल शाका उर्फ गुलनजर,निवासी बहराईच व उसकी पत्नी अमीरल के नाम सामने आया। पुलिस व सर्विलांस टीम ने दोनों अभियुक्तों को मोतीपुर बहराईच के रोडवेज स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है। टीम में एसआई शंकर सिंह रावत,एसआई आशीष रावत,एसआई सुप्रिया नेगी,नैन सिंह,सुरेंद्र रौतेला,गोविंद रौतेला,प्रकाश नगरकोटी,दीपक कापड़ी,शांति गिरी,हेम चंद्र सिंह,कमल तुलेरा शामिल रहे।

जिलाधिकारी ने किया सोमेश्वर तहसील के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण

संवाद सहयोगी

अल्मोड़ा। शनिवार को जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडेय ने सोमेश्वर तहसील के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों और आम जनता की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को प्राथमिकता से समाधान के निर्देश दिए।

जानकारी के अनुसार रनमन में हिमोत्थान (रीप) योजना के तहत उन्होंने महिला शक्ति स्वायत्त सहकारिता के समूहों से संवाद किया और महिलाओं को बकरी पालन, भुट्टा उत्पादन और लाल चावल जैसे व्यवसाय अपनाने की सलाह दी। अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिलाओं को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। स्थानीय लोगों ने बिजली बिल त्रुटि, राशन कार्ड और सड़क मार्ग जैसी समस्याएं उठाईं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। बिजली बिल की शिकायतों के लिए अभियंता को अभियान चलाकर सुधार करने को कहा। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सोमेश्वर का निरीक्षण किया और दवा स्टोर, ओपीडी आदि की स्थिति देखी। कालातीत दवाओं को हटाने और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने के निर्देश दिए। तहसील कार्यालय में उन्होंने खाता-खतौनी, जनाधार समेत अन्य कक्षों का निरीक्षण किया और जनता के कार्य समय पर संपन्न करने के निर्देश दिए। जिनकी जमीन रोड कटान में गई है और मुआवजा नहीं मिला, उनके लिए अभियान चलाकर मुआवजा वितरित करने को कहा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण में कौसानी रोड पर बाघ गधेरे का दौरा किया और पानी निकासी का स्थायी समाधान निकालने के निर्देश दिए। फॉरेस्ट फायर रोकने के लिए सामूहिक सहयोग की अपील की। छानी ल्वेशाल में महिला समूहों से रोजगार बढ़ाने पर चर्चा की और सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनहित के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि सोमेश्वर भुवन जोशी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ आरसी पंत, उपजिलाधिकारी अल्मोड़ा संजय कुमार, तहसीलदार सोमेश्वर नेहा धपोला, अधिशासी अभियंता सिंचाई मोहन सिंह रावत, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत राजेश कुमार, खंड विकास अधिकारी ताकुला खजान चंद्र जोशी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

कैबिनेट मंत्री अग्रवाल के खिलाफ किया प्रदर्शन

संवाद सहयोगी

पौड़ी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल पर पहाड़ी समाज के लोगों को अपशब्द कहने का आरोप लगाते हुए शनिवार को पौड़ी में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित कांग्रेसियों ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का पुतला दहन करते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने सरकार से प्रेमचंद्र अग्रवाल को मंत्री पद से हटाने की मांग भी उठाई। शनिवार को आक्रोशित कांग्रेसियों ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल पर पहाड़ी समाज के लोगों को अपशब्द कहने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यालय से डीएम कार्यालय तक रैली निकाली। डीएम कार्यालय के बाहर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का पुतला फूंका। इस दौरान आक्रोशित कांग्रेसियों ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने पहाड़ी समाज के लोगों के लिए अपशब्द के प्रयोग किए गए। जिससे प्रदेशभर में रहने वाले पहाड़ी समाज के लोगों में आक्रोश बना हुआ है। कहा कि प्रेमचंद्र अग्रवाल कई बार विवादित बयान देते रहे है। उनकी कार्यशैली से प्रदेशवासियों में रोष बना हुआ है। कहा कि सत्ता की हनक में प्रदेश सरकार के मंत्री गलत बयान दे रहे हैं। उन्होंने सरकार से तुरंत प्रेमचंद्र अग्रवाल को मंत्री पद से हटाने की मांग उठाई। प्रदर्शन में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद नेगी, पूर्व नगर अध्यक्ष विनोद बिष्ट, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित सिंह, यशोदा नेगी, विनोद धनोशी, मनमोहन, अमन, गणेश थपलियाल आदि मौजूद रहे।

भू-कानून बनाए जाने पर भाजपाईयों ने जताई खुशी

संवाद सहयोगी

नई टिहरी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड विधानसभा में सख्त भू-कानून पारित होने पर खुशी व्यक्त करते हुए मिठाई बांटी। कहा कि राज्य की जनता लंबे से भू-कानून की मांग कर रही थी। कहा कि सरकार ने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए भू-कानून बना दिया है। शनिवार को जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हनुमान चौक में एक एकत्रित होकर राज्य में सख्त भू-कानून बनाए जाने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लंबे समय से भू-माफिया राज्य के लोगों को झांसा देकर उनकी कीमती जमीन को पौने-पौने दामों में खरीद रहे थे। जिस कारण राज्य के मूल स्वरूप में छेड़छाड़ हो रहा था। राज्य की जनता भी लंबे समय से भू-कानून बनाने की मांग कर रही थी। कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनभावनाओं का सम्मान करते हुए राज्य में सख्त भू-कानून बनाकर सराहनीय कार्य किया है। इस मौके पर डीसीबी के निवर्तमान अध्यक्ष सुभाष रमोला, जिला महामंत्री उदय रावत, राजेंद्र जुयाल, देवेंद्र बेलवाल, डॉ.प्रमोद उनियाल, गोविंद रावत, गिरीश बंठवाण, हर्षमणी सेमवाल, शीशराम थपलियाल, विजय कठैत, रमेश रतूड़ी, प्रताप गुसाईं, सुशील चंद्र बहुगुणा, संदीप रावत, अजयपाल नेगी, हीरा नेगी, असगर अली, ऋषि भट्ट, अनुज डबराल, शांति खंडूरी आदि मौजूद थे।

उपनिबंधक कार्यालय में दस्तावेज लेखकों, अधिवक्ताओं का प्रदर्शन

संवाद सहयोगी

रुद्रपुर। सितारगंज उपनिबंधक कार्यालय के अधिवक्ता व दस्तावेज लेखकों ने यूसीसी के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण एवं वसीयतनामा की प्रक्रिया को सीएससी सेंटरों में देने का विरोध किया है। शनिवार को आयोजित बैठक में प्रक्रिया जटिल कर दी गयी है। अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन किया गया है। भविष्य में रजिस्ट्री प्रक्रिया को पेपरलैस करने का विरोध किया। वक्ताओं ने कहा कि भविष्य में उपनिबंधक कार्यालय से जुड़े अधिवक्ता व दस्तावेज लेखक बेरोजगार हो जायेंगे। यहां अधिवक्ता सौरभ सक्सेना, गौरव सक्सेना, महेंद्र सिंह बसनाल, अनिल सिंह राणा, मो. फैसल, आजम अली, कमल समद्दार, कौशल सक्सेना, जयमल सिंह कालसी, पूरन सिंह फर्त्याल, मो. जाकिर, गौरव बेलवाल, सुरेंद्र सिंह शामिल रहे।

अधिवक्ता और दस्तावेज लेखक 24 से करेंगे कार्य बहिष्कार-अधिवक्ताओं एवं दस्तावेज लेखकों ने शनिवार को अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 और यूसीसी में अनिवार्य विवाह पंजीकरण, वसीयत पंजीकरण व प्रस्तावित पेपरलेस बैनामा रजिस्ट्री के कार्य में अधिवक्ता एवं दस्तावेज लेखकों को बाहर रखने का विरोध किया है। इस दौरान उन्होंने बैठक कर प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार ने अपना निर्णय वापस नहीं लिया तो वे 24 फरवरी से कार्य बहिष्कार करेंगे। शनिवार को उपनिबंधक कार्यालय परिसर में आयोजित बैठक में कहा कि अपनी मांगों के लिए अधिवक्ताओं व दस्तावेज लेखकों की कोर कमेटी बनाई जाएगी। बैठक के बाद अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों ने प्रदर्शन किया। अध्यक्षता जीवन चंद्र जोशी एडवोकेट ने की। इस दौरान जीवन चंद्र जोशी, आरएस कुशवाह, सुखबीर सिंह, इमरान मलिक, रुखसाना मलिक, एमएस तिवारी, हरिशंकर जोशी, शोभित शर्मा, जितेन्द्र कुमार, अतुल अरोरा, राहुल आर्या, प्रगट सिंह, कैलाश चंद्र जोशी आदि रहे।

कार्यालय:- खण्ड विकास अधिकारी, रुड़की (हरिद्वार)

पत्रांक: 2279/लेखा-1/वि0नि0/निविदा-पत्र/24-25 दिनांक: 22/02/2025

निविदा आमंत्रित सूचना

महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधायक निधि के कोष के अन्तर्गत निम्न निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु ग्रामीण विकास विभाग, सिचाई विभाग एवं लोक निर्माण विभाग एवं शासकीय विभागो में पंजीकृत ठेकेदारों से मुहरबन्द निविदायें दिनांक **06.03.2025** के अपराहन 12.00 बजे तक स्वीकृति कार्यों एवं बजट की प्रत्याक्षा में आमंत्रित की जाती है।, जो उसी दिन अपराहन 2.00 बजे निविदाताओं एवं उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा के साथ निर्धारित धरोहर राशि एन०एस०सी०/एफ०डी०आर०/पासबुक के रूप में जमा होनी अनिवार्य है। किसी भी निविदा को बिना बतायें निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास निहित रहेगा। उक्त तिथि को अवकाश होने की स्थिति में अगले दिवस को निविदा खोली जायेगी।

क्र0 स0	कार्य का नाम	कार्य की अनु0 लागत (लाख में)	3% धरोहर धनराशि (₹ में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (₹ में)	कार्य करने की अवधि	ठेकेदार की श्रेणी
1	मरगूबपुर में मेन रोड इकबाल के मकान तक, मेन रोड से मुस्लिम के मकान तक, मेन रोड से मुसर्रत के मकान तक इन्टरलोकिंग टाइल्स सडक निर्माण कार्य ।	5.71	17500	500 + GST	3 माह	डी एवं उच्च
2	ग्राम ब्रहमपुर में रविदास मन्दिर के प्रागण में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	8.26	25000	1000 + GST	3 माह	डी एवं उच्च
3	बावली कल्जरी भारापुर में सहदेवपुर वाले मोड से टीनू के खेत की ओर सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	13.07	40000	1500 + GST	3 माह	डी एवं उच्च
4	ग्राम पाडली तेल्लीवाला रिजवान के मकान के पास आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण कार्य।	5.24	16000	500 + GST	3 माह	डी एवं उच्च
5	ग्राम हकीमपुर तुर्रा में मेन रोड से शहीद के मकान की ओर सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	8.44	25500	1000 + GST	3 माह	डी एवं उच्च
6	ग्राम रामपुर में मेन रोड से अताउर रहमान के मकान की ओर सी०सी०सड़क निर्माण कार्य।	2.83	9000	500 + GST	3 माह	डी एवं उच्च
7	ग्राम बढेडी में साहिल की दुकान से इम्तयाज उर्फ पप्पु के कार्यालय तक इन्टरलांकिग टाईल्स का निर्माण कार्य। (राज्य वित्त)	2.89	9000	500 + GST	3 माह	डी एवं उच्च

निविदा की शर्तें–

1– निविदाये प्रकाशन की तिथि से निविदा खोलने की तिथि तक प्रत्येक कार्य दिवस में विकास खण्ड से नकद मूल्य पर क्रय की जा सकते है।
2– निविदा के समय 100.00 (एक सौ रूपये) के नाम जुडिशियल स्टाम्प रू0 1.00 का टिकट ठेकेदार का हस्ताक्षरयुक्त संलग्न होना अनिवार्य है।
3– निविदा दर स्पष्ट से अंकित होनी चाहिये।
4– अपूर्ण एवं सशर्त निविदा किसी भी दशा में मान्य नही होगी।
5– बिल के भुगतान के समय नियमानुसार आयकर जी०एस०टी०, लेबर सेस रायल्टी की कटोती की जायेगी।
6– एफ०डी०आर०/सी०डी०आर०/एन०एस०सी० खण्ड विकास अधिकारी रूडकी के नाम से बन्धक होगी।
7– निविदा उक्त दिनांक तक इस कार्यालय समय से क्रय की जा सकती है।
8– निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त परफोरमेंस की एफ०डी०आर० प्रस्तुत कर इस कार्यालय से अनुबन्ध 01 सप्ताह के अन्दर करना होगा। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

(सुमन कुटियाल दत्ताल)
खण्ड विकास अधिकरी, रूड़की (हरिद्वार)

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी एवं सम्पादक **एम हसीन** द्वारा परम नागरिक प्रकाशन, 449 (254) शेखपुरी, रुड़की-247667 जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) के लिए ए के प्रिंटर्स खान मार्केट शहाबुद्दीनपुर रोड लद्धावाला, मुजरफ्फरनगर से मुद्रित एवं 449 (254) शेखपुरी, रुड़की-247667 जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित। सम्पर्क : 9997178556 ई-मेल : paramnagrik2013@gmail.com, hasin.m1@gmail.com
सभी वादों का न्याय क्षेत्र रुड़की ही मान्य होगा। प्रकाशित समाचार सामग्री का प्रेस से कोई सम्बंध नहीं है।

मंत्री प्रेमचंद की टिप्पणी पर अल्मोड़ा में आक्रोश, निकाली सांकेतिक शवयात्रा

संवाद सहयोगी

अल्मोड़ा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ के लोगों पर की गई विवादास्पद टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज के नेतृत्व में शनिवार को नाराजगी प्रकट की। कांग्रेसजनों ने जीआईसी से चौघानपाटा तक सांकेतिक शवयात्रा निकालकर चौघानपाटा पर अग्रवाल का प्रतीकात्मक शवदाह किया।

कांग्रेस जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज ने कहा कि वित्त मंत्री ने पहाड़ियों का अपमान किया है, जो उनके मानसिक संतुलन खो जाने का संकेत है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों का राज्य निर्माण में योगदान अविस्मरणीय है और इस प्रकार की टिप्पणी राज्य के आंदोलनकारियों का अपमान है। भोज ने चेतावनी दी कि पहाड़ के लोग इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। भूपेंद्र सिंह भोज ने भाजपा को चुनौती दी कि उनकी पार्टी के मंत्री हिम्मत है तो पहाड़ का दौरा करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उन्हें अल्मोड़ा जिले की सीमाओं में घुसने नहीं देगी और मुख्यमंत्री को ऐसे पहाड़-विरोधी मंत्री से तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए। कार्यक्रम में कांग्रेस नगर अध्यक्ष तारा चंद्र जोशी, महिला जिला अध्यक्ष राधा बिष्ट, प्रदेश सेवा दल महिला अध्यक्ष शोभा जोशी और युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष दीपक कुमार आदि सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं लमगड़ा चौराहे में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा सदन में पहाड़ियों के लिए की गई आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा और क्षेत्रीय लोगों के द्वारा प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। सभी ने एकस्वर में मंत्री प्रेमचंद के बयान पर आक्रोश जताया। यहाँ पुतला दहन कार्यक्रम में पूरन पांडे, राजेंद्र विलवाल, विशन राम, सूरज रावत, पूरन राम, विनोद कुमार, हिमांशु नगरकोटी, दिनेश जोशी, दीपक रावत आदि मौजूद रहे।

एसएसपी अल्मोड़ा ने छात्रों को किया ड्रग्स के प्रति के प्रति जागरूक

अल्मोड़ा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेन्द्र पींचा ने शनिवार को स्प्रिंगडेल्स स्कूल के छात्रों के साथ पुलिस ऑफिस सभागार में ड्रग्स जागरूकता और करियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने जीवन में अनुशासन और रुचि के अनुसार करियर चुनकर कड़ी मेहनत से लक्ष्य पाने की प्रेरणा दी। एसएसपी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी दी और छात्रों के ड्रग्स व करियर से जुड़े सवालों के जवाब देकर उनकी शंकाएं दूर कीं। उन्होंने छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों से बचने और ड्रग्स पैडलरों की सूचना देकर पुलिस का सहयोग करने को प्रेरित किया। कार्यक्रम में हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई और शिकायतकर्ताओं की पहचान गोपनीय रखने का भरोसा दिलाया गया।

दन्या पुलिस ने अवैध शराब के साथ 01 व्यक्ति को किया गिरफ्तार

अल्मोड़ा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र पींचा के निर्देश पर जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री पर सख्त कार्रवाई के लिए नियमित रूप से प्रभावी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत दन्या पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। थानाध्यक्ष जसविंदर सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को दन्या पुलिस टीम ने टकोली बैण्ड, आरासल्पड़ रोड पर चेकिंग के दौरान संदीप जोशी पुत्र प्रेम बल्लभ निवासी मयोली दन्या अल्मोड़ा को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। संदीप जोशी के कब्जे से 07 बोतल बाजपुर गुलाब देशी शराब और 12 अध्धे 8पीएम गोल्ड अंग्रेजी शराब बरामद की गई। इस मामले में थाना दन्या में आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। यहाँ पुलिस टीम में अपर उपनिरीक्षक बीना कौर, कांस्टेबल प्रेम सिंह और कांस्टेबल विनोद डंडरियाल शामिल थे।

वहीं यूपीसीएल के कार्य में बाधा डालने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ग्राम कौली में यूपीसीएल की ओर से कार्य किया जा रहा था। जिसमें कौली कन्याल निवासी कल्याण सिंह बार-बार बिजली विभाग के काम में बाधा डाल रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कल्याण को गिरफ्तार किया। वहीं सल्मोडा बैंड के पास पुलिस ने दुकान संचालक नरेंद्र चंद को अवैध शराब बेचने पर गिरफ्तार किया है।

सड़क हादसे में स्कूटी चालक की मौत के आरोप में टाटा मैजिक चालक पर केस दर्ज

रुद्रपुर। सड़क दुर्घटना में स्कूटी चालक की मौत के आरोप में छोटा वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। हेमा देवी पत्नी खुशाल सिंह धामी निवासी शान्तिपुरी 1 किच्छा ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसके पति खुशाल सिंह धामी पुत्र खड़क सिंह बीती दो फरवरी रात्रि साढ़े ग्यारह बजे वह स्कूटी पर सवार होकर अपने घर शांतिपुरी आ रहे थे। इस दौरान प्राग फार्म के निकट सामने से आ रहे छोटा हाथी वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस घटना में खुशाल सिंह की मौत हो गयी। हेमा देवी ने पुलिस से छोटा हाथी वाहन के चालक के खिलाफ कार्यवाही मांग की। पुलिस ने केस दर्ज किया है।

नानकमत्ता पब्लिक स्कूल को मिला विप्रो अर्थियन अवॉर्ड

संवाद सहयोगी

रुद्रपुर। नानकमत्ता पब्लिक स्कूल को अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय बेंगलुरु में शनिवार को पर्यावरण शिक्षा के लिए विप्रो अर्थियन अवॉर्ड 2024 से सम्मानित किया गया। इससे पहले 2023 में भी नानकमत्ता पब्लिक स्कूल को वेस्ट पर काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। शनिवार को बेंगलुरू में नानकमत्ता पब्लिक स्कूल के संस्था अध्यक्ष चंद्रशेखर अटवाल, नेचर साइंस इनिशिएटिव के रिद्धिमा और मुकेश को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनुराग बहर और विप्रो फाउंडेशन के ट्रस्टी पीएस नारायण ने पुरस्कार दिया। उत्तराखंड ने दूसरी बार यह अवॉर्ड जीता है। दो साल तक लगातार सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन पर काम करने वाली पांच छात्राओं शीतल, जिया, अदिति, हर्षिता और अंजलि की टीम को देहरादून स्थित पर्यावरण शिक्षा के लिए काम करने वाली संस्था नेचर साइंस इनिशिएटिव के दिशा निर्देशन में वेस्ट पर किए गए महत्वपूर्ण काम के लिए इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। छात्राओं के ग्रुप को पीरियड्स के दौरान सेनेटरी नैपकिन से मेंस्ट्रुअल कप की तरफ बदलाव से पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों पर किए गए दो साल के काम के लिए यह अवॉर्ड दिया गया है। पांचों छात्राओं की उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा होने के कारण वे यह पुरस्कार लेने बेंगलुरु नहीं जा सकीं

कूड़ा निस्तारण में लापरवाही बर्दास्त नहीं होगी : डीएम

संवाद सहयोगी

पौड़ी। जिलाधिकारी डा. आशीष चौहान ने एनआईसी कक्ष में जल जीवन मिशन योजना के तहत जिले में हो रहे विकास कार्यों और ब्लाक स्तर पर कूड़े के निस्तारण को लेकर समीक्षा बैठक की।

डीएम ने कहा कि जिन ब्लॉकों में कूड़े के निस्तारण को लेकर कॉम्पेक्टरों का संचालन नहीं किया जा रहा है उनका संचालन तत्काल शुरू करें। ब्लॉकों में कूड़े के निस्तारण को लेकर जिला पंचायत द्वारा कार्य नहीं किए जाने पर अपर मुख्य अधिकारी को चेतावनी जारी की। उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए ब्लॉकों में कूड़े के निस्तारण को लेकर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। डीएम ने अगरोड़ा, जयहरीखाल, दुगड्डा, थलीसैंण और नैनीडांडा क्षेत्र में कूड़े के निस्तारण के लिए लगे कॉम्पेक्टरों का संचालन शुरू करने के निर्देश देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बने सार्वजनिक शौचालयों को चालू अवस्था में रखने, जल जीवन मिशन कार्यों के शेष कार्यों को जल्द पूरा करने, पाइप लाइनों व पेयजल टैंकों के निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश दिए। डीएम ने जल संस्थान पौड़ी और कोटद्वार के अधिकारियों को पेयजल की शिकायतों को लेकर कंट्रोल रूम स्थापित करने, जिन गांवों में वैकल्पिक स्त्रोत कम हैं ऐसे गांवों की कार्ययोजना तैयार कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। बैठक में बताया कि जल जीवन मिशन योजना के तहत 2933 में से 1838 गांवों में पेयजल प्रमाणित हो चुका है। बैठक में वर्चुअल माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, अधीक्षण अभियंता जल निगम मो. मिशम, जल संस्थान प्रवीण सैनी आदि शामिल रहे।

रोजगार मेले में 35 अभ्यर्थियों का चयन

रुद्रपुर। पूर्णागिरी शिक्षा महाविद्यालय झनकट में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में विभिन्न सेक्टर जैसे बैंकिंग, उत्पादन, रियल स्टेट, लिपिक, बीमा आदि क्षेत्रों से संबंधित कंपनियों ने भागीदारी की। इसमें 35 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। शनिवार को पूर्णागिरी शिक्षा महाविद्यालय में विभिन्न क्षेत्रों से आए 178 अभ्यर्थियों ने रोजगार के लिए अपना पंजीकरण कराया। इसमें से 35 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। 100 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। एमडी डॉ. पूनम सिंह ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर उन्हें शुभकामनाएं दीं। इस दौरान डॉ.भास्कर कुकरेती, बलदेव प्रसाद, सुमेरा रहमान, अम्बिका मिश्रा, रवि गंगवार, दिलबाग सिंह, दलजीत सिंह आदि रहे।

23 को निरंकारी मिशन की अमृत परियोजना के तहत स्वच्छता अभियान

संवाद सहयोगी

अल्मोड़ा। बाबा हरदेव सिंह के जन्मदिन पर निरंकारी मिशन के स्वयं सेवक देश भर में रविवार 23 फरवरी को स्वच्छता अभियान चलाएंगे। मिशन की अमृत परियोजना के तहत अल्मोड़ा में कोसी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलेगा। निरंकारी मिशन ने पत्रकार वार्ता में जानकारी दी। अल्मोड़ा में मिशन के संयोजक खीम सिंह रैकुनी ने बताया करीब 96 वर्ष पहले 1929 में निरंकारी मिशन की स्थापना हुई थी। मिशन के सेवादार हर वर्ष देश भर में रक्तदान शिविर, सफाई, पौध रोपण अभियान चलाते हैं। रक्तदान के लिए मिशन के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज है। संस्था के स्वयंसेवक बाढ़, भूस्खलन, तूफान आदि आपदाओं के समय सेवा देते हैं। कई स्थानों पर मिशन अस्पतालों के माध्यम से जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहा है। संचालक रामप्रकाश निरंकारी ने बताया कि मिशन पूरे देश में स्वच्छता को लेकर अमृत परियोजना चला रहा है। इसके तहत रविवार को देश के चुनिंदा 900 शहरों के 1600 स्थानों पर 10 लाख सेवादार साफ सफाई में जुटेंगे। उन्होंने बताया अल्मोड़ा के कोसी बाजार और नदी किनारे स्वच्छता अभियान चलेगा। इस काम में 150 से अधिक मिशन के सेवादार और स्थानीय जनता भागीदारी करेगी। यहाँ पत्रकार वार्ता में तारा बिष्ट, माया गुरुंग, सुरेश पांडे, नंदा बल्लभ तिवारी, स्नेहा निरंकारी आदि मौजूद रहे।

बेहड़ ने निकायों में तैनात कर्मियों के नियमितीकरण का उठाया मुद्दा

संवाद सहयोगी

रुद्रपुर। विधायक तिलकराज बेहड़ ने शुक्रवार को देहरादून में बजट सत्र में नियम 300 की सूचना के तहत निकायों में तैनात कर्मचारियों का मुद्दा उठाया।

बेहड़ ने कहा कि उत्तराखंड निकायों में तैनात संविदा, आउटसोर्स और दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारी पिछले 15-20 वर्षों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे है। कर्मचारी अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर लम्बे समय से आंदोलन कर रहे हैं। शहरी विकास निदेशालय के निदेशक ने 30 नवंबर 2024 को प्रदेश की समस्त निकायों में शासन की बिना अनुमति के कार्यरत संविदा, आउटसोर्स, समिति और दैनिक वेतन पर तैनात कर्मचारियों को चिह्नित कर हटाये जाने के लिए निकायों को आदेश दिया था। जबकि इन कर्मचारियों को शहर की सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था और कार्यालय की आवश्यकता को देखते हुए पालिका बोर्ड की सहमति से रखा गया था। शासन इसे अवैध मान रहा है। बेहड़ ने आरोप लगाया कि इस प्रकार के शासनादेश से कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और कर्मचारियों व उनके परिवारों को नौकरी जाने का भय सता रहा है। बताया कि दस वर्ष से निरंतर कार्य कर रहे कर्मचारी नियमितीकरण की श्रेणी में आते हैं। बेहड़ ने ठेका प्रथा समाप्त कर कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग की। बेहड़ ने बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निकायों में कर्मचारी नियुक्त है। जबकि वर्तमान में जनसंख्या अत्यधिक बढ़ गई है। उन्होंने वर्तमान जनसंख्या को देखते हुए निकाय में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मांग की।

लौका, गोठा के ग्रामीणों का धरना 315वें दिन भी जारी

रुद्रपुर। तीन सूत्रीय मांगों को लेकर लौका, गोठा के ग्रामीणों का शनिवार को धरना 315वें दिन भी जारी रहा। ग्रामवासी काबिज भूमि में भूमिधरी अधिकार देने, गांव में पुलिस चौकी खोलने, गांव में उप चिकित्सालय खोलने की मांग को लेकर नगरपालिका परिसर में अनिश्चितकालीन दिन-रात धरना दे रहे हैं। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सतेन्द्र कुमार ने सरकार, शासन, प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि आंदोलन को 315 दिन हो गये हैं। लेकिन शासन, प्रशासन के किसी अधिकारी ने बात करने की सुध तक नहीं ली। चेतावनी दी कि ग्रामीण आंदोलन तेज करेंगे। यहां मुरारी, योगेंद्र, श्यामसुन्दर, सुरेश, मनोहर, संदीप शामिल रहे।

अधिवक्ताओं ने फूंकी अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 की प्रतियां

संवाद सहयोगी

रुद्रपुर। सितारगंज में अधिवक्ताओं का कार्यबहिष्कार तीसरे दिन भी जारी रही। सिविल कोर्ट परिसर में बार एससोसिएशन के अध्यक्ष दयानंद के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने शनिवार को धरना दिया। यहां हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार अनावश्यक रूप से न्यायपालिका में हस्तक्षेप करना चाहती है जिसको लेकर अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 लाया जा रहा है। जिससे अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता पर कुठाराघात होगा। अधिवक्ताओं ने कहा कि किसी भी रूप में केंद्र सरकार का न्यायपालिका में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिवक्ताओं ने सिविल कोर्ट परिसर में संशोधन बिल 2025 की प्रतियों में आग लगाकर अपना विरोध प्रकट किया। यहां हरीश दुबे, रवि सक्सेना, राहुल, प्रकाश पांडे, मनोरमा, उर्मिला, फरमान, राम बदन सागर, हरीश शर्मा, भगवत सिंह, निकिता ,मोहम्मद हनीफ, राधेश्याम शर्मा, अफसर अली, एसके सिंह, फहीम पटौदी, रमेश कांत प्रभाकर, गुरमीत सिंह, प्रकाश ढाली, सरिता, सुरेंद्र गिरधर, राजेंद्र कुमार, शक्ति प्रताप सिंह, फैजल मलिक, रवि सागर, राजवंत कौर, पुरुषोत्तम सिंह मौजूद रहे।

वहीं दूसरी ओर उप निबंधक कार्यालय में दस्तावेज लेखकों, अधिवक्ताओं का प्रदर्शन-सितारगंज उप निबंधक कार्यालय के अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों ने यूसीसी के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण एवं वसीयतनामा की प्रक्रिया को सीएससी को देने का विरोध कर प्रदर्शन किया। शनिवार को आयोजित बैठक में अधिवक्ताओं ने कहा कि अब प्रक्रिया जटिल कर दी गई है। अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन किया गया है। भविष्य में रजिस्ट्री प्रक्रिया को पेपरलेस करने का विरोध किया। वक्ताओं ने कहा कि भविष्य में उप निबंधक कार्यालय से जुड़े अधिवक्ता एवं दस्तावेज लेखक बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार ने अपना निर्णय वापस नहीं लिया तो वे 24 फरवरी से कार्य बहिष्कार करेंगे। शनिवार को उपनिबंधक कार्यालय परिसर में आयोजित बैठक में कहा कि अपनी मांगों के लिए अधिवक्ताओं व दस्तावेज लेखकों की कोर कमेटी बनाई जाएगी। बैठक के बाद अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों ने प्रदर्शन किया। अध्यक्षता जीवन चंद्र जोशी एडवोकेट ने की। इस दौरान जीवन चंद्र जोशी, आरएस कुशवाह, सुखबीर सिंह, इमरान मलिक, रुखसाना मलिक, एसएस तिवारी, हरिशंकर जोशी, शोभित शर्मा, जितेन्द्र कुमार, अतुल अरोरा, राहुल आर्या, प्रगट सिंह, कैलाश चंद्र जोशी आदि रहे। यहां अधिवक्ता सौरभ सक्सेना, गौरव सक्सेना, महेंद्र सिंह बसनाल, अनिल सिंह राणा, मो. फैसल, आजम अली, कमल समद्दार, कौशल सक्सेना, जयमल सिंह कालसी, पूरन सिंह फर्त्याल, मो. जाकिर, गौरव बेलवाल, सुरेंद्र सिंह मौजूद रहे।

रुद्रप्रयाग में हुआ न्यूरो केयर सेंटर का शुभारंभ

संवाद सहयोगी

रुद्रप्रयाग। मुख्यालय में संगम न्यूरो केयर सेंटर का विधिवत शुभारंभ हो गया है। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष संतोष रावत ने इस सेंटर का शुभारंभ किया। हालांकि यह निजी सेवा के रूप में संचालित है, किंतु नसों से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को इससे बड़ी राहत मिली है।

जानकारी के अनुसार मुख्यालय स्थित बेलनी पुल के समीप संगम न्यूरो केयर सेंटर में हर शनिवार को एमवीवीएस, एमडी, न्यूरो फिजिसाइकेटिक्स डॉ अरविन्द्र सिंह औलख कैंप लगाकर सेवाएं देंगे। पहले ही दिन यहां 50 से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया और दवा ली। बता दें कि जनपद ही नहीं पूरे गढ़वाल क्षेत्र में न्यूरो की सुविधा उपलब्ध नहीं है जिससे मरीजों को देहरादून, दिल्ली और अन्य शहरों की ओर भागना पड़ता है। ऐसे में भले ही निजी तौर पर सेवा मिली हो किंतु लोग इसे राहत समझ रहे हैं। संगम न्यूरो केयर के संचालक डॉ राहुल नौटियाल ने बताया कि हर शनिवार को डॉ अरविन्द्र औलख केयर सेंटर में मौजूद रहेंगे और नगर के साथ ही जनपद वासियों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करेंगे। जो नसो के इलाज में मरीजों की मदद करेंगे।

वहीं पशु चिकित्सालय जाखपुरान में गोट वैली और ब्रायलर फार्म योजना के लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी योगेश कुमार शर्मा ने गोट वैली योजना में लाभार्थियों को प्रबंधन, आहार, टीकाकरण एवं दवा पान आदि की जानकारी दी। पशुपालकों से बकरी और मुर्गी की आपूर्ति आईटीबीपी को कर आजीविका बढ़ाने को कहा। उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी लाल सिंह सामंत ने पशुपालकों को शासन की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। ब्रायलर फॉर्म स्वामियों ने आईटीबीपी को जिंदा मुर्गी उपलब्ध कराने को लेकर वार्ता की

सम्पादकीय

परम नागरिक

रविवार, 23 फरवरी, 2025

जिम्मेदारियों का निर्वहन अधिकारियों के जेहन

सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर वरिष्ठों के बर्ताव को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की डांट-फटकार को इरादतन किया गया अपमान नहीं माना जा सकता, जिस पर आपराधिक कार्यवाही की जरूरत हो। ऐसे मामलों में व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक आरोप लगाने की अनुमति देने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पीठ ने कहा महज गाली-गलौच, असभ्यता व अशिष्टता भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत आदतन किया गया अपमान नहीं है। यह धारा शांति भंग करने के इरादे से जान-बूझकर अपमान करने से संबंधित है, जिसमें दो साल की सजा का प्रावधान है। मामले में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान के कार्यवाहक निदेशक पर सहायक प्रोफसर को अपमानित करने का आरोप था। शिकायतकर्ता के अनुसार निदेशक ने अन्य कर्मचारियों के समक्ष डांटा व फटकारा था। यह सच है कि कार्यस्थल से संबंधित अनुशासन और कर्तव्यों के निर्वहन से जुड़ी फटकार, जो व्यक्ति कार्यस्थल पर प्रबंधन करता है, वह अधीनस्थों से अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा व समर्पण से पूरी करने की उम्मीद करेगा। हालांकि स्पष्ट तौर पर देखने में आता है कि अनुशासन के नाम पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों के साथ संतुलित बर्ताव का अभाव नजर आता है। लहजा गलत हो भी तो नीयत बुरी नहीं होनी चाहिए, परंतु इस बारीक अंतर को समझना या समझा पाना भी आसान नहीं है। सेना के सख्त अनुशासन के दरम्यान कई बार ऐसी खबरें आती रहती हैं, जहां नीचे के ओहदे के सैनिक द्वारा अपने अधिकारी की हत्या तक कर दी गई। तय रूप से काम का दबाव, उच्च दर्जे की तामील, पाबंदियां और तय वक्त पर जिम्मेदारियों का निर्वहन अधिकारियों के जेहन पर खासा दबाव बनाते हैं। वे भी तनावग्रस्त या काम के बोझ के चलते सामान्य बर्ताव करने से चूक सकते हैं। यहां बात सिर्फ उच्चाधिकारियों या कनिष्ठों तक ही सीमित नहीं है। कार्य-स्थल पर अभद्र भाषा या गाली-गलौच करने वाले अशिष्ट अधिकारियों के बर्ताव को लेकर भी कर्मचारी क्षुब्ध रहते हैं। ज्यों कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले उत्पीडन व अभद्र बर्ताव को लेकर कानून बनाए गए हैं। वैसे ही समस्त कर्मचारियों के हित में भी व्यवहारगत संहिता लागू किए जाने की जरूरत है। मानवता कहती है, ओहदे ऊपर-नीचे होने से दोयम बर्ताव करने का हक किसी को नहीं दिया जा सकता। यह नियम मालिकान व मुलाजिम पर भी लागू होता है।

क्या जघन्य अपराधियों की न सुनी जाये पैरोल की अर्जी?

डॉ. सत्यवान सौरभ

कैदियों की समय से पहले रिहाई से समाज को खघ्तरा हो सकता है, खासकर तब जब वे बार-बार अपराध करते हों। हाल के वर्षों में, इस विचार में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव आया है क्योंकि अमीर और शक्तिशाली वर्ग ने जेल में समय बिताने से बचने के लिए पैरोल का उपयोग करना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर, लाखों अन्य कैदी, जिनके पैरोल के अनुरोधों को अनदेखा किया जाता है, उनके पास प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए संसाधनों की कमी होती है, या उन्हें कमजोर आधारों के आधार पर गलत तरीके से लाभ से वंचित किया जाता है क्योंकि वे गरीब और शक्तिहीन हैं।

पैरोल सुधार और पुनः एकीकरण पर आधारित है, लेकिन जब इसका उपयोग गंभीर अपराधों के लिए किया जाता है, तो यह नैतिक और कानूनी दुविधाएँ पैदा करता है। मानवाधिकारों और पुनर्वास के सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, भले ही न्याय दंड और रोकथाम की मांग करता हो। आपराधिक न्याय प्रणाली में एक महत्त्वपूर्ण कदम पैरोल है। यह कैदियों को समाज में पुनः एकीकृत करने में सहायता करने के लिए दिया जाने वाला एक प्रकार का विचार है। यह कैदी की सामाजिक पुनर्प्राप्ति के लिए एक उपकरण से अधिक कुछ नहीं है। हालाँकि, हाल के वर्षों में, इस विचार में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव आया है क्योंकि अमीर और शक्तिशाली वर्ग ने जेल में समय बिताने से बचने के लिए पैरोल का उपयोग करना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर, लाखों अन्य कैदी, जिनके पैरोल के अनुरोधों को अनदेखा किया जाता है, उनके पास प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए संसाधनों की कमी होती है, या उन्हें कमजोर आधारों के आधार पर गलत तरीके से लाभ से वंचित किया जाता है क्योंकि वे गरीब और शक्तिहीन हैं। चूँकि हमारी जेलें अहिंसक अपराधियों से सचमुच भरी हुई हैं, इसलिए पैरोल से जेल में बंद लोगों को अपने प्रियजनों के साथ अपनी सजा के बचे हुए हिस्से को पूरा करने का मौका मिलता है, जबकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों की उन पर कड़ी नजर रहती है। यह हर दिन लाखों रुपयों की टैक्स बचत करता है और पूरे समाज के लिए एक बेहतरीन व्यवस्था है। बहुत कम बार आप किसी हिंसक अपराधी के बारे में सुनते हैं जो पैरोल पर रिहा हुआ और फिर एक और हिंसक अपराध करने लगा।

ज्यादातर हिंसक अपराधी किसी भी मामले में अपनी सजा का कम से कम 85% हिस्सा पूरा करते हैं। लेकिन इसमें कोई दोराय नहीं है कि पैरोल से पीड़ितों और उनके परिवारों की न्याय की भावना कमजोर हो सकती है। आतंकवाद, बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के खिलाफ मजबूत रोकथाम होनी चाहिए। रोकथाम बनाए रखने के लिए, 2012 के निर्भया मामले के दोषियों को पैरोल नहीं दी गई। कैदियों की समय से पहले रिहाई से समाज को खघ्तरा हो सकता है, खासकर तब जब वे बार-बार अपराध करते हों। बार-बार अपराध करने के कारण, 2013 के शक्ति मिल्स सामूहिक बलात्कार मामले के दोषियों को पैरोल नहीं दी गई। राजनीतिक प्रभाव से न्याय में विश्वास को नुकघ्सान हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप पैरोल की मंजूरी मिलती है जो वारंटेड नहीं होती है। टी. पी. चंद्रशेखरन हत्या मामले में पैरोल कथित तौर पर राजनीतिक दबाव के कारण दी गई थी। इन अपराधों में शामिल क्रूरता और पूर्व-योजना के कारण, सुधार चुनौतीपूर्ण है। 2018 के कठुआ बलात्कार मामले ने स्पष्ट कर दिया कि दया से रहित कठोर दंड की आवश्यकता है। भारतीय न्यायालयों के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पैरोल पर रिहा किए गए लोगों को संतानोत्पत्ति और विवाह के अपने अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति है। हालाँकि, चूँकि विवाह के अधिकार को कानून द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, इसलिए इस आधार पर पैरोल देने से समलैंगिक कैदियों के समानता के अधिकार से समझौता होता है।

सभी कैदियों के लिए समानता और समावेशिता की गारंटी देने के लिए, न्यायालय अनुच्छेद 21 के तहत अंतरंगता के अधिक सामान्य अधिकार से पैरोल को जोड़ सकते हैं। नेल्सन मंडेला नियम (2015), कैदियों के उपचार के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम, का एक प्रमुख घटक सुधार है। पैरोल एक अधिकार है, न कि विशेषाधिकार, जैसा कि न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कई फैसलों में जोर दिया है। सामान्य प्रतिबंध होने के बजाय, व्यवहार मूल्यांकन के आधार पर पैरोल दी जानी चाहिए। आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों के पुनर्वास के परिणामस्वरूप 2023 में महाराष्ट्र में पुनरावृत्ति में कमी आई। पैरोल अनुरोधों का मूल्यांकन न्यायालयों द्वारा पहले से ही योग्यता के आधार पर किया जाता है, जिससे सुरक्षा और न्याय की गारंटी मिलती है। हरियाणा राज्य बनाम जय सिंह (2003) में, सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि पैरोल निष्पक्ष मानकों के अनुसार दी जानी चाहिए। अनुच्छेद 21 (सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार) का उल्लंघन पैरोल की संभावना के बिना जेल में आजीवन कारावास द्वारा किया जा सकता है, यदि सुधार प्रदर्शित किया जाता है। श्रीहरन (2015) के अनुसार, किसी को पैरोल से पूरी तरह से वंचित करना असंवैधानिक है। नॉर्वे जैसे देशों में धीरे-धीरे पुनः एकीकरण पर जोर देकर, यहाँ तक कि जघन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए लोगों के लिए भी पुनः अपराध दर कम हो गई है। पुनर्वास न्याय के अपने मॉडल की बदौलत नॉर्वे में दुनिया में पुनरावृत्ति की सबसे कम दरें हैं।

जैसा कि आमतौर पर जाना जाता है, मजबूत प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव से पैरोल प्रशासन की प्रभावशीलता बाधित हुई है। कार्यक्रम के लक्ष्य से नियमित रूप से समझौता किया जाता है और कई अनुचित अपराधियों को प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में पैरोल दी जाती है। पैरोल के सम्बंध में, एक अच्छी तरह से परिभाषित न्यायिक नीति आवश्यक है और किए गए कार्यकारी कर्तव्यों की अदालतों द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए। हमारे कानून निर्माताओं के लिए हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए आवश्यक बदलाव करने का समय आ गया है। इन बदलावों में कैदियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रगतिशील तरीके से पर्यवेक्षित रिहाई प्रणाली को लागू करने के लिए मजबूत दिशा-निर्देश बनाना, लगातार पैरोल कानून बनाकर यह साबित करना कि यह पुनर्वास के लिए एक प्रभावी उपकरण है और भारत में पैरोल के दुरुपयोग को रोकने के लिए जाँच और संतुलन स्थापित करना शामिल होना चाहिए। सरकार को जेलों में भीड़भाड़ के बारे में चिंतित होना चाहिए और उन्हें तुरंत इस पर गौर करना चाहिए। भयानक अपराधों के लिए पैरोल को सीमित करते समय न्याय, निवारण और पुनर्वास सभी पर विचार किया जाना चाहिए। सख्त न्यायिक निगरानी के साथ पारदर्शी, योग्यता-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके व्यापक प्रतिबंधों के बिना सार्वजनिक सुरक्षा और नैतिक निष्पक्षता की गारंटी दी जा सकती है। पैरोल एक ऐसी चीज है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, जैसा कि स्पष्ट है।

झूठी शादी की शपथ की आड़ में दुष्कर्म

प्रियंका सौरभ

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि हर साल झूठी शादी की शपथ की आड़ में कई हजार बलात्कार के मामले दर्ज किए जाते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अतुल गौतम मामले में 2025 में दिए गए फैसले से यह सवाल उठता है कि न्यायिक व्याख्याएं महिलाओं की स्वायत्तता और कानूनी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती हैं? बलात्कार और सेक्स के लिए सहमति देना स्पष्ट रूप से अलग-अलग है। इन स्थितियों में, न्यायालय को सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या शिकायतकर्ता की पीडिघ्ता से शादी करने की वास्तविक इच्छा थी या उसके कोई छिपे हुए उद्देश्य थे और उसने केवल अपनी वासना को शांत करने के लिए इस आशय का झूठा वादा किया था, क्योंकि बाद वाले को धोखा या छल माना जाता है। इसके अतिरिक्त, झूठा वादा न निभाने और उसे तोड़ देने में अंतर है।

अभियुक्त द्वारा अभियोक्ता को यौन गतिविधि में शामिल होने के लिए लुभाने के इरादे के बिना किया गया वादा बलात्कार के रूप में मान्य नहीं होगा। अभियोक्ता अभियुक्त द्वारा बनाए गए झूठे प्रभाव के बजाय उसके प्रति अपने प्यार और जुनून के आधार पर अभियुक्त के साथ यौन संबंधों के लिए सहमति दे सकती है। वैकल्पिक रूप से, अप्रत्याशित या अनियंत्रित परिस्थितियों के कारण ऐसा करने का इरादा होने के बावजूद अभियुक्त उससे शादी करने में असमर्थ हो सकता है। इन स्थितियों को अलग तरीके से संभालने की जरूरत है। बलात्कार का मामला तभी स्पष्ट होता है जब शिकायतकर्ता का कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा या गुप्त उद्देश्य हो। अतुल गौतम बनाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है। यह फैसला अपर्णा भट बनाम के विपरीत है।

2021 के मध्य प्रदेश राज्य के फैसले में आरोपी और पीडिघ्त को द्वितीयक आघात से बचने के लिए जमानत पर रहते हुए संवाद करने से मना किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी के लिए, जमानत की आवश्यकताओं को आरोपी और उत्तरजीवी के बीच संचार के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। यह विचार कि विवाह बलात्कार के लिए एक उपाय है न कि अपराध के लिए सजा, ऐसी जमानत आवश्यकताओं द्वारा पुष्ट होता है, जो सामाजिक समझौते को कानून के शासन से आगे रखता है। रामा शंकर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) में जमानत देते समय इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसने प्रतिवादी के खिलाफ अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर कर दिया। उत्तरजीवी को जमानत प्राप्त करने के लिए आरोपी द्वारा विवाह के लिए मजबूर किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कानूनी व्यवस्था के भीतर निरंतर र्दु?यवहार हो सकता है।

अभिषेक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024) ने न्याय की गारंटी देने के बजाय, अभियुक्त को विवाह के वादे के बदले में जमानत देकर एक दबावपूर्ण गतिशीलता बनाई। जो उत्तरजीवी को उचित पुनर्वास सहायता प्राप्त करने के बजाय अभियुक्त पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करता है। किशोरों के निजता के अधिकार (2024) में न्यायालय द्वारा उत्तरजीवियों और बच्चों को आवास, शिक्षा और परामर्श प्रदान करने के राज्य के दायित्व पर प्रकाश डाला गया था। जमानत का उद्देश्य सामाजिक कर्तव्यों को लागू करना नहीं है, बल्कि मामला लंबित रहने तक अस्थायी स्वतंत्रता की गारंटी देना है। न्यायालयों ने पिछले कई निर्णयों में एक पीडिघ्त के पुनर्वास को विवाह के बराबर माना है, बलात्कार को शारीरिक स्वायत्तता के उल्लंघन के रूप में स्वीकार करने में विफल रहे। न्यायालय महिलाओं की स्वायत्तता को कमजोर करते हुए अपराधियों के साथ विवाह करने के लिए पीडिघ्तों पर दबाव डालकर कानूनी संरक्षण के तहत र्दु?यवहार और नियंत्रण को बढ़ावा देते हैं। विवाह को उपाय मानने वाली अदालतें पीडिघ्त की सहमति की कमी को नजरअंदाज करती हैं, जिसका अर्थ है कि जबरदस्ती को कानूनी रूप से उचित ठहराया जा सकता है।

महिलाओं को लगातार आघात और सुरक्षा जोखिमों के बावजूद अक्सर अपने र्दु?यवहार करने वालों के साथ श्समझौता विवाह' में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हुए, जो महिलाओं की स्वायत्तता और गरिमा की रक्षा करता है, ऐसे निर्णय महिलाओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध संबंधों में मजबूर करके उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, जबरन विवाह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हैं, जिससे पीडिघ्तों को न्याय के बजाय अधिक शोषण का सामना करना पड़ता है। ये निर्णय इस धारणा को बनाए रखते हैं कि विवाह यौन हिंसा को हल कर सकता है, इन घटनाओं को गंभीर अपराधों के बजाय नागरिक विवादों में बदल देता है। रिश्ते की जटिलता और धोखाधड़ी के इरादे के बीच अंतर करने के लिए एक अच्छी तरह से कानूनी रणनीति की आवश्यकता होती है। कानूनी सुरक्षा को मजबूत करके और लिंग-संवेदनशील न्यायिक प्रशिक्षण प्रदान करके न्याय किया जा सकता है, जो लैंगिक समानता के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

युवा देश में युवा राजनीति का हो नया दौर

किशन सनमुखदास भावनानी

भारत में अपनें मासिक मन की बात रेडियो कार्यक्रम की 113 वीं कड़ी में 25 अगस्त 2024 को माननीय पीएम नें बताया कि लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2024 के संबोधन में बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले एक लाख युवाओं के राजनीति में शामिल होने के आह्वान किया था जिससे युवाओं की ओर से व्यापक प्रतिक्रियाए मिली है। उन्होंने युवाओं से विकसित भारत तथा मजबूत लोकतंत्र के लिए सार्वजनिक जीवन में आने का आग्रह किया था। पीएम ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी समाज के हर क्षेत्र से ऐसे अनेक लोग सामने आए थे जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। इन लोगों ने खुद को भारत की आजादी के लिए झोंक दिया था। आज हमें विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए एक बार फिर उसी भावना की जरूरत है।उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में युवा राजनीति में आने को तैयार बैठे हैं और बस उन्हें सही मौके तथा सही मार्गदर्शन की तलाश है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इसके क्रियान्वयन के लिए 60 प्लस नेताओं को राजनीति से संन्यास लेने के लिए प्रेरित, बंधनकारक, अनिवार्य, जबरन रिटायरमेंट बनाने के लिए हर राजनीतिक दल को सख्त नीति बनाने की आवश्यकता है क्योंकि मैंने अपनी छोटी सी राइस सिटी गोंदिया नगरी में देखा है कि यहां 70 प्लस वाले भी रजिस्टर्ड नवयुवक सेवा मंडल के अध्यक्ष बन रहे हैं, तो 60 प्लस वाले भी रजिस्टर्ड पंचायत, संगठनों, संस्थाओं के अध्यक्ष बने हुए हैं तो कई पर्दे के पीछे 60 प्लस वाले कई संस्थाओं संगठनों परनियंत्रण रखे हुए हैं। फिर पंचायत समिति से लेकर संसद सदस्य तक, और पार्षदसे लेकर केंद्रीय व राज्यस्तर पर मंत्रिमंडल में भी हम 60 प्लस वालों को देख सकते हैं तो फिर लाखों युवा बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि वालों की चांस लगाना क्या संभव है? इसको रेखांकित करना जरूरी है। बता दें वैश्विक स्तरपर किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवा वर्ग एक अहम भूमिका निभाता है। युवा वर्ग शारीरिक और मानसिक रूप से किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक करने में सक्षम होता है। हर व्यक्ति जीवन के इस दौर से गुजरता है। युवाओं को उच्चस्तर की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और विभिन्न क्षेत्रो में अपना योगदान देना चाहिए।किसी भी राष्ट्र में कुल जनसंख्या का 20-30 जबकि भारत में विशेष रूप से 65 प्रतिशत हिस्सा युवा हैं। किसी भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने में युवा वर्ग का सर्वाधिक योगदान रहा है। राष्ट्र की प्रगति विज्ञान, प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य, प्रबंधन और अन्य क्षेत्रों में विकासपर निर्भर होती है। इन सभी मानदंडों को पूरा करने के लिए सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर युवाका सशक्तीकरण आवश्यक है।युवा राष्ट्र का संरचनात्मक और कार्यात्मक ढांचा है। हर राष्ट्र की सफलता का आधार उसकी युवा पीढ़ी और उनकी उपलब्धियाँ होती हैं। राष्ट्र का भविष्य युवाओं के सर्वांगीण विकास में निहित है। इसलिए युवा राष्ट्र निर्माण में सर्वोच्च भूमिका निभाते हैं। जिस तरह से इंजन को चालू करने के लिए इंधन जिम्मेदार होता हैय ठीक उसी तरह युवा राष्ट्र के लिए है। यह राष्ट्र की प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करता है।किसी भी राष्ट्र को प्रौद्योगिकियों, शोध, विज्ञान, चिकित्सा, यानी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक के संदर्भ में प्रगति और विकास के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। जब युवा अपने प्रयासों के साथ ईमानदारी से यही काम करता हैं, तो इसे चिह्नित किया जाता है। भारत में युवाओं की सबसे बड़ी संख्या है, जिन्हें यदि बेहतर तरह से पोषित किया जाये और अगर ये अपना प्रयास सही दिशा में लगाते हैं, तो यह देश पूरी दुनिया में सबसे उत्कृष्ट बन जायेगा। चूंकि आज विकसित भारत बनाने में यंग माइंड्स की प्रभावशाली भागीदारी जरूरी है इसलिए आज हम पीएम के संबोधन का संज्ञान लेकर तथा मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,एक लाख युवाओं को राजनीति में शामिल होने का आह्वान / 60 प्लस को राजनीतिक संन्यास का आह्वान उम्रदराज राजनीतिज्ञ व परिवारवाद की राजनीति में कई गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाली टैलेंटेड प्रतिभाएं दब जाती है।दुनियां में जहां भी बदलाव हुए हैं वहां तरुणाई ने हमेशा नेतृत्व किया है।

साथियों बात अगर हम 25 अगस्त 2024 को माननीय पीएम की मासिक मन की बात की 113 वीं कड़ी में उनके विचारों की करें तो उन्होंने कहा इस साल मैंने लाल किले से बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले एक लाख युवाओं को पॉलीटिकल सिस्टम से जोड़ने का आहवाहन किया है। मेरी इस बात पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है।इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में हमारे युवा, राजनीति में आने को तैयार बैठे हैं। बस उन्हें सही मौके और सही मार्गदर्शन की तलाश है। इस विषय पर मुझे देश-भर के युवाओं के पत्र भी मिले हैं। सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोगों ने मुझे कई तरह के सुझाव भी भेजे हैं। कुछ युवाओं ने पत्र में लिखा है कि ये उनके लिए वाकई अकल्पनीय है।दादा या मातापिता की कोई राजनीतिक विरासत नहीं होने की वजह से,वोराजनीति में चाहकर भी नहीं आ पाते थे।

कुछ युवाओं ने लिखा कि उनके पास जमीनी स्तरपर काम करने का अच्छा अनुभव है, इसलिए, वे लोगों की समस्याओं को सुलझाने में मददगार बन सकते हैं। कुछ युवाओं ने ये भी लिखा कि परिवारवादी राजनीति, नई प्रतिभाओं का दमन कर देती है। कुछ युवाओं ने कहा कि इस तरह के प्रयासों से हमारे लोकतंत्र को और मजबूती मिलेगी। मैं इस विषय पर सुझाव भेजने के लिए हर किसी का धन्यवाद करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अब हमारे सामूहिक प्रयास से ऐसे युवा, जिनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, वे भी राजनीति में आगे आ सकेंगे, उनका अनुभव, और उनका जोश, देश के काम आएगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी समाज के हर क्षेत्र से ऐसे अनेकों लोग सामने आए थे, जिनकी कोई राजनीतिक पृष्टभूमि नहीं थी। उन्होनें खुद को भारत की आजादी के लिए झोंक दिया था। आज हमें विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए एक बार फिर उसी स्पिरिट की जरूरत है। मैं अपने सभी युवा साथियों को कहूँगा इस अभियान से जरूर जुड़ें। आपका ये कदम अपने और देश के भविष्य को बदलने वाला होगा।

साथियों बात अगर हम युवाओं पर भारत की करें तो भारत लोकतंत्र की जननी है। देश की विविधता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हमें अपनी विविधता को सबसे बड़ी ताकत बनाते हुए देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जी-जान से जुटना होगा। वर्तमान समय की यह बड़ी उपलब्धि रही है कि देशवासियों में भारतीयता की सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण हुआ है। इसी सामूहिक चेतना के कारण भारत के विकसित राष्ट्र का संकल्प और मजबूत हो रहा है। आज जन कल्याण से जग कल्याण की राह पर चलने वाला भारत पहला राष्ट्र है। आज समूचा विश्व भारत की तरफ गर्व और अपेक्षा से देख रहा है। वर्तमान कुशल नेतृत्व और त्वरित निर्णय शक्ति के कारण आज दुनिया के शक्तिशाली देश भी तमाम समस्याओं के समाधान के लिए भारत को मार्गदर्शक के तौर पर देखने लगे हैं। राष्ट्र को विकसित बनाने में युवाओं की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भागीदारी हो सकती है। आगामी 25 वर्षो में भारत को विकसित देशों की श्रेणी में शामिल करने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। पीएम का भाषण आजादी के अमृत काल में युवाओं के लिए पथ-प्रदर्शक का कार्य करेगा।आज जब हम आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं तो यह पिछले 75 वर्षो में देश केसंकल्पों को पूरा करने वाले सभी लोगों के योगदान का स्मरण करने का अवसर है। साथ ही अमृत काल के आने वाले 25 वर्षो पर अपनी शक्ति और सामर्थ्य को केंद्रित भी करना है। तभी वर्ष 2047 में एक शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र का सपना साकार होगा। युवा वर्ग देश का भविष्य होने केसाथ-साथ हमारे देश के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में युवाओं की संख्या अन्य देशों से अधिक है।

भारत की लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या की आयु 35 वर्ष से कम है। सरकार का पूरा ध्यान युवाओं के माध्यम से विकास लाने पर केन्द्रित है। उनके अनुसार युवा देश के विकास के लिए अपना सक्रिय योगदान प्रदान करें न कि केवल उसका एक हिस्सा बनकर रह जाएँ। सरकार द्वारा पेश की गई राष्ट्रीय युवा नीति-2014 का उद्देश्य युवाओं की क्षमताओं को पहचानना और उसके अनुसार उन्हें अवसर प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना और इसके माध्यम से विश्वभर में भारत को उसका सही स्थान दिलाना है।युवाओं के व्यक्तित्व में सुधार लाने, उनमें नेतृत्व के गुण विकसित करने एवं उनमें जिम्मेदार नागरिक के गुण और स्वयंसेवा की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से युवा मामले विभाग ने विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वयित किया है। युवा देश की आबादी का सबसे जीवंत और संसाधन पूर्ण हिस्सा है, इनकी सामाजिक, आर्थिक विकास के सशक्तिकरण में महत्वपूर्णभूमिका है।गरीबी से बाहर आने एव आजीविका विकास के लिए उनकी आंतरिक क्षमताओं को बाहर लाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिससे कि वे स्वस्थ एवं सार्थक जीवन यापन कर सकें । पीएम ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो रोडमैप साझा किया, उसे धरातल पर उतारने की पहली जिम्मेदारी देश के युवाओं की है। कहते हैं, जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है।

साथियों बात अगर हम युवा भारत के संबंध में माननीय पीएम के विचारों की करें तो, उन्होंने देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया है। विकसित भारत की इससंकल्पना को साकार रूप देने में युवा आबादी की अहम भूमिका होगी। इस भूमिका के लिए युवाओं को तैयार करने का बीड़ा शिक्षा मंत्रालय ने उठाने का फैसला किया है। इस मिशन के लिए शिक्षा मंत्रालय युवाओं को दो तरह से तैयार करेगा। एक तो उन्हें विकसित भारत मिशन के लिए जागरूक मानवीय शक्ति के रूप में निखारा जाएगा।

मिथिला पालकर ने अपनी पहली तमिल फिल्म यात्रा को बताया विशेष

अभिनेत्री मिथिला पालकर ने अपनी बहुप्रतीक्षित पहली तमिल फिल्म ओहो एंथन बेबी की शूटिंग पूरी कर ली है और अभिनेत्री खुशी और उत्साह से अभिभूत हैं।

अपनी खुशी व्यक्त करते हुए, मिथिला ने कहा, मैंने अपनी पहली तमिल फिल्म पूरी कर ली है और मैं हर किसी के इसे देखने का इंतजार नहीं कर सकती! ऐसा लगता है जैसे कल ही हमने मुहूर्त शॉट शूट किया था और अब, हमने शूटिंग पूरी कर ली है - यह एक अद्भुत एहसास है। यह यात्रा वास्तव में खास रही है, न केवल इसलिए कि यह मेरी पहली तमिल फिल्म है, बल्कि इसलिए भी कि मुझे उन अविश्वसनीय लोगों के साथ काम करने का मौका मिला।

उन्होंने आगे कहा तमिल में अपनी लाइनें सीखना निश्चित रूप से एक चुनौती थी, लेकिन मैंने इसका पूरा आनंद लिया। मेरे सह-कलाकार रुद्र, मेरे निर्देशक कृष्णकुमार रामकुमार और पूरी कास्ट और क्रू ने मुझे बहुत स्वागत और घर जैसा महसूस कराया, भले ही मैं तमिल भाषा नहीं बोल पाता। उनके निरंतर समर्थन और गर्मजोशी ने इस प्रक्रिया को बहुत आसान और और भी मजेदार बना दिया. मिथिला ने आगे कहा, सिर्फ फिल्मांकन के अनुभव से परे, मुझे संस्कृति में डूबने का मौका मिला, मैंने अपना ज्यादातर समय यहाँ बिताया और इस दौरान बहुत कुछ सीखा। यह फिल्म सीखने और विकास की यात्रा रही है, और मैं अपने दर्शकों को इस नए अवतार में देखने के लिए बेताब हूँ!

'ओहो एंथन बेबी' का निर्देशन कृष्णकुमार रामकुमार ने किया है और इसका निर्माण रेमियो पिक्चर्स,

विष्णु विशाल और डी कंपनी ने किया है।

इस बीच, मिथिला पालकर हाल ही में फिल्म 'स्वीट ड्रीम्स' में नजर आईं, जहाँ उन्होंने गीतकार दीया का किरदार निभाया। विक्टर मुखर्जी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सपनों की असली दुनिया से जुड़े दो अजनबियों की कहानी है। इस फिल्म में अमोल पाराशर, मेयांग चांग और सौरसेनी मैत्रा भी थे।

'स्वीट ड्रीम्स' 24 जनवरी को डिज्नी+ हॉटस्टार पर रिलीज हुई।

फिल्म के बारे में बात करते हुए मिथिला ने कहा, दीया की कहानी ऐसी है जिससे हममें से कई लोग खुद को जोड़ पाएंगे क्योंकि वह भ्रमित है, महत्वाकांक्षी है और कुछ और पाने की चाहत रखती है। केनी के साथ उसके जो सपने हैं, वे सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं हैं; वे यह समझने के बारे में हैं कि वास्तव में क्या मायने रखता है। इस फिल्म की शूटिंग करना एक भावनात्मक यात्रा की तरह लगा।

पीरियड ड्रामा फिल्म कांथा से भाग्यश्री बोरसे की फर्स्ट लुक आउट

कांथा की निर्माताओं ने मुख्य नायिका भाग्य श्री बोरसे का पहला लुक कुछ समय पहले ही जारी किया गया है। पहली तस्वीर में भाग्य श्री बोरसे एक खूबसूरत बैठी हुई मुद्रा में दिखाई दे रही हैं। पारंपरिक लुक में दिख रही उनकी आकर्षक अदाओं ने दर्शकों का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया है। वैलेंटाइन डे स्पेशल पोस्टर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। मलयालम स्टार दुलकर सलमान और टॉलीवुड स्टार राणा दग्गुबाती की जोड़ी वाली पीरियड ड्रामा कांथा की घोषणा कुछ महीने पहले ही की गई थी। फ़िलहाल, शूटिंग तेजी से चल रही है। कांथा का निर्देशन सेल्वामणि सेल्वराज कर रहे हैं, फिल्म का निर्माण डीक्यू वेफेयरर फिल्म्स और

स्पिरिट मीडिया ने मिलकर किया है। फिल्म का संगीत प्रशांत ने तैयार किया है और इसमें अभिनेता समुथिरकानी प्रमुख भूमिका में हैं। राणा दग्गुबाती इस फिल्म को प्रस्तुत कर रहे हैं।

मलाइका अरोड़ा ने दिखाया मदमस्त अंदाज

बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस और फैशनिस्ट मलाइका अरोड़ा आए दिन अपनी लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं। उनका हर एक लुक इंटरनेट पर आते ही तेजी से वायरल होने लगता है। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों में उनका ग्लैमरस लुक देखकर फैंस के होश उड़ गए हैं।

एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा अपने बोल्ड फिगर और क्लासी फैशन स्टेटमेंट्स के कारण सोशल मीडिया पर लाइमलाइट में बटोरती रहती हैं। वो जब भी अपनी फोटोज इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हैं तो फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं।

अब हाल ही में एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने अपनी लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं। इन तस्वीरों में उनका किलर और गॉर्जियस

लुक देखकर फैंस एक बार फिर से बेकाबू हो गए हैं।

मलाइका अरोड़ा की लेटेस्ट तस्वीरों में आप देख सकते हैं उन्होंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई है, जिसमें वो ग्लैमरस और हॉट लुक में पोज देती हुई नजर आ रही हैं।

बालों को ओपन कर के, लाइट मेकअप और न्यूड शेड लिपस्टिक लगाकर एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने अपने आउटलुक को बेहद ही शानदार तरीके से कंप्लीट किया है।

एक्ट्रेस की इन फोटोज को शेयर हुए कुछ ही घंटे हुए हैं और अब तक कई सारे यूजर्स ने फोटोज पर लाइक्स कर दिए हैं। वहीं, एक यूजर ने कॉमेंट करते हुए, लिखा है- टू मच हॉट। दूसरे यूजर ने लिखा है- बोल्ड एंड ब्यूटिफुल मल्ला।

मलाइका अरोड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी फैन फॉलोइंग लिस्ट भी काफी जबरदस्त है। एक्ट्रेस 51 साल की हो गई हैं, लेकिन आज भी अपनी हॉटनेस से इंटरनेट पर तबाही मचाती रहती हैं।

शबाना आजमी और ज्योतिका स्टारर डब्बा कार्टेल का टीजर हुआ रिलीज

काफी समय से अभिनेत्री शबाना आजमी अपनी आगामी वेब सीरीज डब्बा कार्टेल को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं, जिसके निर्देशन की कमान हितेश भाटिया ने संभाली है। फरहान अख्तर इसके निर्माता हैं। शबाना के अलावा इस सीरीज में गजराज राव, ज्योतिका और साईं ताम्हणकर जैसे कलाकार भी अभिनय करते नजर आएंगे। अब आखिरकार निर्माताओं ने डब्बा कार्टेल का टीजर जारी कर दिया है, जिसमें शबाना की अदाकारी की खूब तारीफ हो रही है। टीजर को प्रशंसक पसंद कर रहे हैं। डब्बा कार्टेल ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। सीरीज की रिलीज तारीख से भी पर्दा उठ गया है। डब्बा कार्टेल को आप 28 फरवरी से नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे।

निर्माताओं ने टीजर साझा करते हुए लिखा, आज डब्बे में क्या है?

इस सीरीज में निमिषा सजयन, शालिनी पांडे, अंजलि आनंद, जिशु सेनगुप्ता, लिलेट दुबे और भूपेन्द्र सिंह जादावत भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। टीजर में तमाम सितारों की झलक दिख रही है।

सनम तेरी कसम के बाद हर्षवर्धन राणे ने अनाउंस की

नई लव स्टोरी दीवानियत, आया सामने टीजर

हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन की सनम तेरी कसम की री-रिलीज ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है. इसी बीच हर्षवर्धन ने एक और रोमांटिक लव स्टोरी का एलान किया है. खास बात ये है कि उन्होंने इसकी घोषणा प्यार के दिन वैलेंटाइन डे पर की है जिसमें उन्होंने वादा किया कि फिल्म रोमांचक और दिल को झकझोर देने वाली होगी.

सनम तेरी कसम की अपार सफलता के बाद अब हर्षवर्धन दीवानियत लेकर आ रहे हैं जिसकी अनाउंसमेंट उन्होंने एक शानदार मोशन पोस्टर रिलीज करते हुए की है. मोशन पोस्टर में एक खून से लथपथ हाथ में एक गुलाब का फूल है. इसके साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, हमारी

अपकमिंग फिल्म की घोषणा, दीवानियत हर्षवर्धन राणे स्टारर एक दिल को झकझोर कर देने वाली म्यूजिकल लव स्टोरी, सनम तेरी कसम की री-रिलीज की ग्रैंड सक्सेस के बाद. बता दें फिल्म को 2025 को अंत तक रिलीज किए जाने की योजना है.

हर्षवर्धन राणे ने आगामी फिल्म के लिए अपनी उत्सुकता दिखाते हुए कहा, मैं दर्शकों का आभारी हूं कि उन्होंने सनम तेरी कसम के लिए मुझे इतना प्यार दिया है. एक लव स्टोरी काफी पावरफुल होती है, जब मैंने दीवानियत में अपने रोल और कहानी के पागलपन, जुनून को सुना, तो मैंने तुरंत इसे अपनी अगली फिल्म के रूप में चुना. उन्होंने आगे कहा, मैं अपने निर्देशक मिलाप मिलन जावेरी और निर्माता अमूल वी मोहन, अंशुल मोहन के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हूं. उम्मीद है कि दर्शकों को भी यह दिल तोड़ने वाली लव स्टोरी पसंद आएगी.

हाई-वोल्टेज स्टोरीटेलिंग (सत्यमेव जयते, मरजावां) के मास्टर मिलाप मिलन जावेरी द्वारा निर्देशित और मुश्ताक शेख (ओम शांति ओम) द्वारा लिखित यह फिल्म बड़े पर्दे पर जुनून और दिल टूटने की एक एपिक कहानी का वादा करती है. इस म्यूजिकल लव स्टोरी के लिए लीड एक्ट्रेस की घोषणा जल्द की जाएगी. द साबरमती रिपोर्ट के मेकर्स द्वारा बनाई गई दीवानियत इस साल फ्लोर पर जाने के लिए तैयार है और इसे 2025 के अंत तक सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.

आदर्श गौरव की सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव का ट्रेलर जारी

सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. ट्रेलर में एक ऐसी कहानी है जिसमें कुछ लडके अपनी आम जिंदगी से उठकर कुछ बड़ा करने का सोचते हैं और अपने ही गांव यानि मालेगांव में फिल्म बनाने का सोचते हैं. जिसका नाम है- मालेगांव की शोले. ट्रेलर की शुरुआत में एक प्लेन को देखकर दो दोस्त उसके बारे में बात करते हैं कि क्या चीज बनाई है और वे उसमें बैठने का सपना देखते हैं. इस फिल्म में आदर्श गौरव, शशांक अरोड़ा, अनुज सिंह दुहान, साकिब अयूब, विनीत कुमार सिंह, पल्लव सिंह जैसे कलाकार हैं. जो बात करते हैं मुंबई जाने की लेकिन इनमें से एक बोलता है कि मुंबई जाने की क्या जरुरत है हम यहीं अपने गांव में मुंबई को ले आते हैं. यहीं पिक्चर बनाते हैं. घर से उनको सख्त हिदायत मिल जाती है कि जो बनाना है बनाओ लेकिन घर से एक पैसा नहीं मिलेगा. कुछ दोस्त कहते हैं कि हम खजूर की दुकान चलाते हैं, हम लोग जन्म गरीब हैं, पिक्चर बनाने का कैसे सोच सकते हैं. लेकिन एक दोस्त सबको मोटिवेट करता है कि हम कुछ अलग कर सकते हैं, जो हमारा अपना हो और फिर सब साथ हो जाते हैं और फिल्म बनाने की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है- मालेगांव की शोले. सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव को कई फिल्म फेस्टिवल में तारीफ मिल चुकी है. फिल्म मालेगांव के आम लोगों की है जिसमें नासिर शेख अपने दोस्तों के साथ फिल्म बनाने का सपना देखता है और उसे पूरा करता है. अब देखना है कि थिएटर में दर्शक इसे कैसा रिस्पॉन्स देते हैं. फिल्म को रीमा कागती ने निर्देशित किया है और इसे रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर, जोया अख्तर, रीमा कागती ने प्रोड्यूस किया है.

बॉक्स ऑफिस पर जुनैद-खुशी की फिल्म लवयापा का बंटाधार

आमिर खान के बेटे जुनैद खान और जाह्नवी कपूर की बहन खुशी कपूर की फिल्म लवयापा को 7 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. यह फिल्म इसलिए खास है, क्योंकि यह बड़े पर्दे पर दोनों की पहली फिल्म है।

इस फिल्म से निर्माताओं को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर इसका हाल-बेहाल है। फिल्म का कारोबार लाखों में सिमटा हुआ है।

आइए बताते हैं लवयापा ने सातवें दिन कितने लाख रुपये कमाए।

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, लवयापा ने अपनी रिलीज के छठे दिन यानी पहले बुधवार को 35 लाख रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स

ऑफिस कलेक्शन 6.50 करोड़ रुपये हो गया है।

लवयापा के निर्देशक अद्वैत चंदन हैं। यह तमिल रोमांटिक कॉमेडी लव टुडे का रीमेक है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था।

इस फिल्म में ग्रुशा कपूर, आशुतोष राणा और किकू शारदा जैसे कलाकारों भी हैं।

बॉक्स ऑफिस पर लवयापा का सामना हिमेश रेशमिया की फिल्म बैडएस रवि कुमार से हो रहा है। अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स और शाहिद कपूर की फिल्म देवा भी इन दिनों सिनेमाघरों में लगी हुई है।

इसके अलावा विक्की कौशल फिल्म छावा के साथ दर्शकों के बीच हाजिर हो गए है।

इस फिल्म में रश्मिका मंदाना, अक्षय खन्ना, आशुतोष राणा, विनीत कुमार, दिव्या दत्ता और डायना पेंटी जैसे सितारे भी नजर आ रहे हैं।

फिल्म द डिप्लोमैट का ट्रेलर जारी

भारत की बेटी को बचाने खतरनाक मिशन पर निकले जॉन अब्राहम

बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम और सादिया खातीब अभिनीत फिल्म द डिप्लोमैट का बहुप्रतीक्षित ट्रेलर रिलीज हो गया। दिवंगत सुषमा स्वराज की जयंती पर रिलीज किया गया यह ट्रेलर 2017 में उनके द्वारा भारत की बेटी को वापस लाने में भारतीय राजनयिक जेपी सिंह का समर्थन करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों को श्रद्धांजलि देता है।

यह राजनीतिक थ्रिलर फिल्म इस बात के बारे में बताती है कि युद्ध के बजाय चतुराई और बातचीत नायक के अंतिम हथियार हैं। जॉन अब्राहम वास्तविक जीवन के भारतीय राजनयिक जेपी सिंह की भूमिका में हैं, जो भारत की बेटी को कैद से छुड़ाने के लिए एक उच्च-दांव मिशन पर निकलते हैं। शिवम नायर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में

जॉन अब्राहम ने रणनीति, बुद्धिमत्ता और बातचीत पर आधारित एक ऐसा किरदार निभाया है, जिसे उन्होंने बड़े पर्दे पर पहले कभी नहीं निभाया है।

फिल्म के बारे में बात करते हुए जॉन ने कहा, कूटनीति एक युद्ध का मैदान है, जहां शब्दों का वजन हथियारों से ज्यादा होता है। जेपी सिंह की भूमिका निभाने से मुझे एक ऐसी दुनिया का पता लगाने का मौका मिला जहां शक्ति को बुद्धि, लचीलापन और शांत वीरता से परिभाषित किया जाता है। उजमा की कहानी भारत की ताकत और साहस का प्रमाण है और मुझे इस प्रेरक यात्रा को स्क्रीन पर जीवंत करने पर गर्व है।

द डिप्लोमैट की कहानी, पटकथा और संवाद रितेश शाह ने लिखे हैं। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी डिमो पोपोव और एमएसपी ग्यड ने की है, जबकि संपादन कुणाल वाल्वे ने किया है। रवि श्रीवास्तव प्रोडक्शन डिजाइन की देखरेख की है। डैनियल बी जॉर्ज ने फिल्म के लिए मूल संगीत तैयार किया है, जबकि ध्वनि डिजाइन मोहनदास वीपी द्वारा किया गया है। फिल्म का मूल संगीत ए.आर. रहमान ने दिया है और गीत मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं। कलाकारों में रेवती, कुमुद मिश्रा और शारिब हाशमी भी शामिल हैं। यह फिल्म 7 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

काबीना मंत्री की टिप्पणी पर कोटद्वार में भड़के लोग

संवाद सहयोगी

कोटद्वार। काबीना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा शुक्रवार को विधानसभा देहरादून में किये गये व्यवहार के बाद अब लोगों का आक्रोश शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को इसके विरोध में सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने आंखों में पट्टी बांधकर और कानों में रूई डालकर प्रदर्शन करते हुए तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की गई।

पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रमेश भंडारी ने कहा कि काबीना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान पर्वतीय समाज के प्रति उनकी नफरत को दर्शाता है। कहा कि जिन पहाड़ियों के वोट से आज मंत्री बने हुए हैं उन्हीं के प्रति इस तरह की भाषा का प्रयोग करना अनुचित है। पार्षद सूरज प्रसाद कांति ने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल पिछले कार्यकाल में विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं इसके बावजूद खुलेआम सड़क पर मारपीट और उनके ही कार्यकर्ताओं द्वारा उनके खिलाफ सड़क पर गाली-गलौज जैसे किस्से पहले भी हो चुके हैं। इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए।

प्रदर्शन करने वालों में राम कंडवाल, मनमोहन खंतवाल, महावीर नेगी, जितेन्द्र बिष्ट, राकेश नेगी, आशीष विश्नोई, अर्जुन रावत, दीपक रावत आदि शामिल रहे। उधर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी इस मामले में काबीना मंत्री का पुतला दहन कर तत्काल मंत्री पद से हटाने की मांग की।

भू कानून से ध्यान भटकाने को कांग्रेस कर रही है विभाजन की राजनीति

संवाद सहयोगी

देहरादून। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस भू कानून की उपलब्धि से ध्यान भटकाने के लिए विभाजनकारी राजनीति की ओर बढ़ रही है। उन्होंने इसे प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि कांग्रेस को विकास से कोई मतलब नहीं है और अनावश्यक मुद्दों को तूल देखकर समाज को पहाड़- मैदान में बांटना चाहती है। शनिवार को पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ध ामी के नेतृत्व में कई ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, जिन्हें कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। राज्य में लंबे समय से सशक्त भू कानून की मांग चल रही था। सीएम धामी ने बजट सत्र में यह कानून लाने का ऐलान किया था और इसे विधानसभा में पारित करा कर अपने एक और वादे को पूरा किया है। इससे पूरे राज्यभर में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसदीय कार्य मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ रहे हैं। मंत्री इस पर खेद भी जता चुके है। कहा कि कांग्रेसी विधायकों का आचरण सबने देखा, लेकिन कांग्रेस के इन निरंकुश विध ायकों को रोकने के लिए कोई नहीं था। चौहान ने कहा कि अगर, कांग्रेसी इतने ही पहाड़ और उत्तराखंड के शुभचिंतक हैं तो भू कानून का इतिहास बनने पर प्रदेशवासियों की तरह जश्न क्यों नहीं मना रहे हैं?

साइकिल रैली से दिया मतदाता जन जागरुकता का संदेश

देहरादून। निर्वाचन आयोग की ओर से शनिवार को देहरादून में मतदाता जागरूकता साइकिल रैली आयोजित की गई। इसमें करीब 250 साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। पुलिस लाइन रेसकोर्स देहरादून से मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने रैली को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने खुद भी रैली में हिस्सा लिया। 20 किलोमीटर रैली में लोगों को मतदाता जनजागरुकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मतदाता शपथ के साथ हुई। जिसके बाद साइकिल रैली पुलिस लाइन से आराघर चौक, ईसी रोड, राजपुर रोड, कैनाल रोड, काटबंगला पुल होते हुए वापस पुलिस लाइन ग्राउंड पहुंची। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य मतदाताओं को उनके स्वास्थ्य और मताधि कारों के प्रति जागरुक करना है।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर प्रेम चंद्र का पुतला फूंका

संवाद सहयोगी

काशीपुर। देशी-पहाड़ी के मुद्दे पर विधानसभा में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की आपत्तिजनक बयानबाजी से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश भड़क उठा। उन्होंने अग्रवाल पर उत्तराखंड विरोधी होने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और एमपी चौक पर पुतला फूंका। शनिवार को दर्जनों कार्यकर्ता महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन और पूर्व महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल के नेतृत्व में एकत्र हुए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा के नेता सत्ता के नशे में चूर होकर लगातार अमर्यादित बयान बाजी करते हैं। सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य के स्थाई निवासियों के बारे में अभद्र टिप्पणी की है। कहा, राज्य का अपमान करने वाले कैबिनेट मंत्री अग्रवाल को उत्तराखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने की बात कही है। यहां ब्रह्मसिंह पाल, शिवम शर्मा, अफसर अली, अनीस अंसारी, शिवम् उपाध्याय, हनीफ गुड्डू, अजीता शर्मा, शेख मोहम्मद, सैफ मोहम्मद, मिर्जा अकरम बेग, रवि पपनै, शादान, गुल्लू माहीगीर व अनिल शर्मा आदि रहे।

वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ मियांवाला चौक पर प्रदर्शन किया। उक्रांद के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट ने कहा कि पहाड़ी समाज को गाली देने वाले विधायक को तत्काल विधानसभा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। युवा नेता परवीन चंद रमोला ने कहा कि कैबिनेट मंत्री का पहाड़ियों को अपमानित कर मैदान पहाड़ की बात करना इनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है स केंद्रीय महामंत्री बृजमोहन सजवाण ने कहा कि पहाड़ के विधायकों को कैबिनेट मंत्री का विरोध करना चाहिए।

मंत्री अग्रवाल के खिलाफ राज्य आंदोलनकारियों ने किया प्रदर्शन

संवाद सहयोगी

विकासनगर। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के बैनर तले राज्य आंदोलनकारियों ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर उत्तराखंड के मूल निवासियों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया।

राज्य आंदोलनकारियों का आरोप है कि मंत्री लगातार पहाड़ियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। आंदोलनकारियों ने मंत्री को सरकार से बर्खास्त करने की मांग की है। सत्येंद्र चौक पर प्रदर्शन के दौरान राज्य आंदोलनकारी अमित पंवार ने कहा कि राज्य सरकार में जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कैबिनेट मंत्री की मानसिकता पहाड़ और उत्तराखंड के मूल निवासियों को लेकर दुर्भावनापूर्ण है। उन्होंने कहा कि मंत्री ऋषिकेश से विधायक हैं, जहां बहुसंख्यक आबादी पहाड़ मूल की है। जिन लोगों ने उन्हें जीत दिलाकर मंत्री पद तक पहुंचाया आज वह उन्हीं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर पहाड़ के मूल बाशिंदों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि खुद को अनुशासित पार्टी बताने वाली भाजपा के मंत्री और विध ायक अक्सर उत्तराखंड के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते रहते हैं। इससे पहले पूर्व विधायक प्रणव चौंपियन भी उत्तराखंड के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पहाड़ के मूल बाशिंदों और उत्तराखंड के खिलाफ टिप्पणी करना देवभूमि का अपमान है। राज्य आंदोलनकारी अमित पंवार ने कहा कि पहाड़ में वो लोग रहते हैं, जो बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल के मंदिर में पूजा-अर्चना करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल की पवित्र भूमि पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आंदोलनकारियों ने मंत्री को सरकार से बर्खास्त करने की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में दिनेश तिवारी, अशोक नेगी, हरीश बिष्ट, संजीव उपाध्याय, चमन मनोगा, चरण सिंह आदि शामिल रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल द्वारा पहाड़ के लोगों के खिलाफ अपशब्द प्रयोग करने के विरोध में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। नाराज कार्यकर्ताओं ने बुद्ध पार्क में प्रदर्शन कर मंत्री का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मंत्री को जल्द अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल, महानगर कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद बिष्ट आदि मौजूद रहे।

वहीं दूसरी ओर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान को लेकर आक्रोशित कांग्रेस ने शनिवार को दून में अलग-अलग स्थानों पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सदन में जिस तरह का व्यवहार मंत्री ने किया है, उसे देखते हुए नैतिकता के आधार पर मंत्री का इस्तीफा लिया जाना चाहिए।

दून को स्वच्छ और सुंदर बनाने में छात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण

संवाद सहयोगी

देहरादून। दून शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में छात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण है। स्कूलों में ही उन्हें जैविक अजैविक कूड़ा अलग से देने और प्लास्टिक वेस्ट कम करने को लेकर विस्तार से जानकारी दी जाए तो इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। यह बात शनिवार को नगर निगम सभागार में स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत आयोजित कार्यशाला में नगर आयुक्त नमामी बंसल ने कही। अधिकारी ने कहा कि कई हाउसिंग सोयायटी,एनजीओ, सामाजिक संगठन, अपने स्तर पर सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में बेहतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दून को स्वच्छ और सुंदर बनाने का लक्ष्य तभी प्राप्त हो पाएगा जब जैविक-अजैविक कूड़े का अलग से निस्तारण करने और प्लास्टिक की रोकथाम को शुरू किए गए अभियान व्यापक स्तर पर चलें। उन्होंने कहा कि जापान के तर्ज पर यदि स्कूलों में ही छात्रों को स्वच्छता को लेकर व्यवहारिक जानकारी दी जाए तो उसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिनके यहां कंपोस्ट मशीन लगी हैं, वह आसपास के लोगों को भी सफाई को लेकर जागरूक करें। एसडीसी फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल ने प्लास्टिक बैंकों के माध्यम से किए जा रहे प्लास्टिक वेस्ट के निस्तारण को लेकर जानकारी दी। होटल मधमुबन के प्रतिनिधि और अन्य एनजीओ के पदाधिकारियों ने बताया कि वह अपने स्तर से कैसे योजनाबद्ध तरीके से कूड़ा निस्तारण का कार्य कर रहे हैं या छात्रों व लोगों को जागरूक कर रहे हैं। एमआईएस एक्सपर्ट रजत भंडारी ने स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी दी। नगर आयुक्त ने कहा कि कोई भी एनजीओ, संगठन आदि निगम को सुझाव दे सकते हैं। ताकि आपसी समन्वय से पूरे सौ वार्डों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें। इस दौरान सहायक नगर आयुक्त राजबीर सिंह चौहान, मुख्य सफाई निरीक्षक, सफाई निरीक्षक आदि मौजूद थे।

मुख्यमंत्री के बालश्रम एवं भिक्षावृत्तिमुक्त उत्तराखण्ड के सकंल्प को चरितार्थ करते डीएम देहरादून

देहरादून। मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार पुष्कर सिंह धामी के भिक्षावृत्तिमुक्त उत्तराखण्ड सोच पर जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल निरंतर आगे बढ रहे हैं। जिलाधिकारी निर्देशन में आज दिनांक 22/02/2025 को बालश्रम मे लिप्त एक बालिका व चार बालकों को सेलाकुई से भिक्षावृत्ति रेस्क्यू टीम देहरादून द्वारा रेस्क्यू किया गया बच्चों कि प्राथमिकी व मेडिकल करवा कर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें एक बालिका को राजकीय बालिका निकेतन में ओर चार बालक को समर्पण (खुला आश्रय) में रखवाए गए। वहीं भिक्षावृत्ति/कूड़ा बीनने में लिप्त एक बालक एक बालिका को माता वाला बाग, लालपुल से भिक्षावृत्ति में व तीन बालकों को बाल श्रम करते हुये राजीव नगर डाँड़ा, जैन प्लॉट से भिक्षावृत्ति रेस्क्यू टीम देहरादून द्वारा रेस्क्यू किया गया।

फर्जी कागजों के आधार पर भूमि हड़पने का आरोप, चार पर केस

संवाद सहयोगी

काशीपुर। एक व्यक्ति ने चार नामजद तथा एक अज्ञात के खिलाफ फर्जी कागजों के आधार पर उसकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव बिराहा फार्म निवासी नवतेज सिंह शोकर ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसकी मामी रजवंत कौर निवासी गांव संतोषपुर के गांव हरिपुरा में खसरा संख्या 443 में भूमि है। बताया था कि उसकी मामी ने 16 दिसंबर 2024 को उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी जिसके बाद उसकी मामी रजवंत कौर कनाडा चली गई। आरोप लगाया कि वह 9 नवंबर 2024 को खेत में जुताई कर रहा था कि इस दौरान मौके पर चार लोग पहुंचे। आरोपियों ने बताया कि यह भूमि उन्होंने खरीद ली है। हरिपुरा गांव निवासी अनिल सेन नाम के एक व्यक्ति ने जमीन का सौदा कराया है। जब उन्होंने सब रजिस्ट्रार कार्यालय से जानकारी ली तब पता चला कि उसकी मामी रजवंत कौर के स्थान पर किसी अन्य महिला ने अपने को रजवंत कौर बताकर जमीन का बैनामा भागरथी बसेड़ा के नाम कराया था। अन्य लोग गवाह भी दर्शाए गए हैं। उसने मिलीभगत और साजिश के तहत आरोपियों पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। उसने प्रकरण की लिखित शिकायत कोतवाली बाजपुर को दी। उसके बाद एसएसपी को डाक से प्रेषित की गई।

आयुष के फलक पर बिखरी उत्तराखंड की चमक

संवाद सहयोगी

देहरादून। आयुष के बडेध् फलक पर उत्तराखंड की चमक बिखरी है। पहाड़ के लाल और देश के जाने-माने आयुर्वेद, जड़ी-बूटी विशेषज्ञ डॉ० मायाराम उनियाल को केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने प्रतिष्ठित धन्वंतरी पुरस्कार प्रदान किया है। देशभर के सिर्फ तीन विशेषज्ञों को यह पुरस्कार दिया गया है। दूसरी तरफ, आयुष मंत्रालय के बेहद महत्वपूर्ण प्रकृति परीक्षण अभियान के पहले चरण में उत्तराखंड को उसके प्रयासों के लिए सराहना मिली है। पूरे प्रदेश में डेढ़ लाख लोगों का प्रकृति परीक्षण किया गया है।

मुंबई में आयुष मंत्री ने किया डॉ उनियाल का सम्मान-केंद्रीय आयुष मंत्रालय की ओर से 20 फरवरी को मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में डॉ० मायाराम उनियाल को यह पुरस्कार दिया गया। केंद्रीय आयुष मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने प्रताप राव जाधव ने डॉ० उनियाल के साथ ही आयुर्वेद विशेषज्ञ प्रताप डॉ० ताराचंद व डॉ० जमदग्नि को धनवंतरी पुरस्कार प्रदान किया। इस पुरस्कार के अंतर्गत विशेषज्ञों को पांच-पांच लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई है। डॉ० उनियाल को इससे पहले, आयुष मंत्रालय की ओर से प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया जा चुका है। उन्होंने आयुर्वेद, जड़ी-बूटी के क्षेत्र में कई शोध किए हैं। डॉ० उनियाल का कहना है कि जब से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी आसीन हुए हैं, तब से आयुष क्षेत्र ने गति पकड़ी है। उन्होंने कहा कि आयुष के क्षेत्र में उत्तराखंड तमाम संभावनाओं से भरा हुआ है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय के बेहद महत्वपूर्ण प्रकृति परीक्षण अभियान के पहले चरण में उत्तराखंड में डेढ़ लाख लोगों का प्रकृति परीक्षण किया गया है। इस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था। इस अभियान के तहत उत्तरकाशी के महीडांडा जैसे सीमांत इलाके में स्थित आईटीबीपी की पोस्ट तक भी आयुष टीम पहुंची और जवानों का प्रकृति परीक्षण किया। राज्य समन्वयक डॉ० जेएन नौटियाल के अनुसार-विपरीत भौगोलिक स्थितियों के बावजूद डेढ़ लाख लोगों का उत्तराखंड में प्रकृति परीक्षण किया गया है। इसकी सराहना हुई है। उत्तराखंड समेत सभी राज्यों के समन्वयकों को मंत्रालय के स्तर पर सम्मानित किया गया है। देश ने पार किया एक करोड़ का निर्धारित लक्ष्य-प्रकृति परीक्षण अभियान में पूरे देश में एक करोड़ लोगों के प्रकृति परीक्षण का लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य से ज्यादा एक करोड़ 29 लाख लोगों का प्रकृति परीक्षण किया गया है। इस अभियान में केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉच किया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन कराने के बाद संबंधित व्यक्ति से बातचीत के आधार पर उसकी प्रकृति का निर्धारण किया जा रहा है। वात, कफ व पित्त की स्थिति का आंकलन करके संबंधित व्यक्ति की प्रकृति उसे बताई जा रही है। इसके साथ ही, आयुर्वेद चिकित्सक संबंधित व्यक्ति को उसकी प्रकृति के अनुरूप आहार-विहार का परामर्श दे रहे हैं। डॉ०आशुतोष गुप्ता, सचिव देश का प्रकृति परीक्षण अभियान का कहना है कि देश के प्रकृति परीक्षण अभियान में लक्ष्य से ज्यादा लोगों का परीक्षण किया गया है और कई कीर्तिमान बने हैं। कठिन भौगोलिक स्थितियों वाले उत्तराखंड राज्य ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए अच्छे प्रयास किए हैं। इस अभियान का दूसरा चरण गतिमान है। लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए यह अभियान उपयोगी साबित होगा।

पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आयुष के क्षेत्र में देश निरंतर प्रगति कर रहा है। देश के प्रकृति परीक्षण अभियान को पहले चरण में मिली सफलता उत्साहित करने वाली है। इससे लोगों का जीवन निरोगी व स्वस्थ होगा। मैं इस अभियान से जुड़े समस्त लोगों और पुरस्कृत होने वाले विशेषज्ञों को हार्दिक बधाई देता हूं।